आयोजन

भारत-नेपाल मित्रता का पैगाम

सोरघाटी एक बार फिर भारत-नेपाल मित्रता की गवाह बनी। कार्यक्रम था काव्योत्सव का जिसमें दोनों देशों के पचास से अधिक साहित्यकारों और कवियों ने अपनी रचनाओं के जरिए मित्रता का पैगाम दिया

पृष्ठ 9

कैप्टा

अडानी को 'सुप्रीम' राहत

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के लिए यह साल चौतरफा सौगात लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग रिसर्च मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से न कराकर सेबी से ही जारी रखने के आदेश कर दिए हैं। इसे अडानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है

पृष्ठ 11

दि संडे पोस्ट

2001 से प्रकाशित

07 जनवरी से 13 जनवरी 2024, मूल्य : 3:00

हर रविवार को देहरादून से प्रकाशित

ना काहू से दोस्ती - ना काहू से बैर

वर्ष 15, अंक : 30, उत्तराखण्ड संस्करण (पृष्ठ 16)

वेबसाइट www.thesundaypost.in

श्वेत क्रांति पर भ्रष्टाचार की कालिख

आवरण-कथा

अमूल की सफलता से प्रसन्न होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन से कहा था कि अमूल के मॉडल को देश के अन्य हिस्सों में भी फैलाया जाए और इसके लिए वे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नेतृत्व करें। प्रधानमंत्री के आग्रह पर वर्गीज कुरियन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासनिक हस्तक्षेप और लाल फीताशाही से बचाते हुए इसके मुख्यालय को दिल्ली से दूर किसानों के बीच स्थापित किया था। फिलहाल उत्तराखण्ड में श्वेत क्रांति की बात करें तो स्वायत्तता और पेशेवर नेतृत्व का कुछ ऐसा ही माहौल यहां की एकमात्र सरकारी अधिपत्य वाली आंचल डेयरी को भी चाहिए था। लेकिन ऐसा माहौल प्रदेश के सियासत दां देने में नाकामयाब साबित हुए हैं। पशुपालकों को स्वरोजगार के सपने के साथ शुरू हुई उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन सियासत और भ्रष्टाचार का शिकार हो चली है। राज्य के दूध ब्रान्ड 'आंचल' का आंचल दागदार हो चुका है। डेयरी का संचालन भ्रष्ट तंत्र के जाल में है। आरोप लग रहे हैं कि जो कभी दुग्ध उत्पादक नहीं रहे उनके संचालन में आंचल का दूध मैला होने के साथ ही मिलावटी हो चला है। इसकी पुष्टि लैब में फेल दूध के सैम्पल करते हैं। दुग्ध और डेयरी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का नेटवर्क इतना मजबूत है कि जांच रिपोर्ट में आई सच्चाई भी नक्कारखाने में तूती की आवाज बन कर रह गई है

पृष्ठ 5, 6

बाबरी मस्जिद विध्वंस से राममंदिर तक

भारतीय राजनीति की बदलती दशा और दिशा

राम पुनियानी
लेखक राष्ट्रीय एकता मंच के संयोजक हैं।

यह वह समय है जब हमें नेहरू के 'आधुनिक भारत के मंदिरों' की संकल्पना और वैज्ञानिक समझ के विस्तार और विकास के प्रयासों को याद करना चाहिए। इस समय धार्मिकता और अंधश्रद्धा को जबरदस्त बढ़ावा दिया जा रहा है। जब हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को तोड़ा था, तब हमने यह संकल्प लिया था कि 'अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति' हमारा फोकस होगा। परंतु आज राजनीति अयोध्या के राममंदिर के आस-पास घूम रही है और उसके बाद, काशी और मथुरा तो बाकी हैं ही। ऐसे में 'अंतिम व्यक्ति' की किसे चिंता है? नेहरू ने 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' में जो वायदे किए थे, वे सब भुला दिए गए हैं और देश की हर समस्या, हर असफलता के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताया जा रहा है

स्वाधीन होने के बाद भारत ने जो दिशा और राह चुनी, उसकी रूपरेखा जवाहरलाल नेहरू के 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' भाषण में थी। नेहरू ने कहा, 'भारत की सेवा का अर्थ है लाखों-लाख पीड़ितों की सेवा। भारत की सेवा का अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना। हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा तो यही है कि हर आंख से हर आंसू पोछा जाए। यह हमारे बस की बात न भी हो, तब भी, जब तक आंसू हैं और पीड़ा है, हमारा काम खत्म नहीं होगा।'

और इसी संदर्भ में उन्होंने भाखडा नंगल बांध का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में आधुनिक भारत के मंदिरों की बात कही 'हिंदुस्तान टाइम्स' अखबार ने लिखा, 'अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में प्रधानमंत्री ने इन स्थानों को मंदिर और आराधना स्थल बताया जहां हजारों लोग, अपने दसियों लाख बंधुओं के कल्याण की खातिर एक बड़ी रचनात्मक गतिविधि में रत हैं।'

'आधुनिक भारत के मंदिर' - यह वाक्यांश उस थीम को अपने में समेटे हुए था जो सार्वजनिक क्षेत्र की परिकल्पना का आधार थी और जिस थीम के भाग के रूप में वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई, अस्पताल बनाए गए और संस्कृति के उन्नयन के लिए विभिन्न अकादमियों का गठन किया गया। 'आधुनिक मंदिरों' के निर्माण का सिलसिला करीब चार-पांच दशक तक चलता रहा।

सन १९८० के दशक में इस प्रक्रिया को पलट दिया गया। इस दशक में अल्पसंख्यकों की खातिर शाहबानों फैसले को पलटने के सरकार के निर्णय से विघटनकारी राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक ताकतों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रचार युद्ध छेड़ दिया। इसके साथ ही, पिछड़ों और दमितों के कल्याण के लिए सकारात्मक कदम के रूप में मंडल आयोग की रपट लागू करने के निर्णय ने मंदिर राजनीति, जो पहले से ही हिंदू राष्ट्रवादियों के रणनीतिक एजेंडा का हिस्सा थी, को जबरदस्त बल दिया।

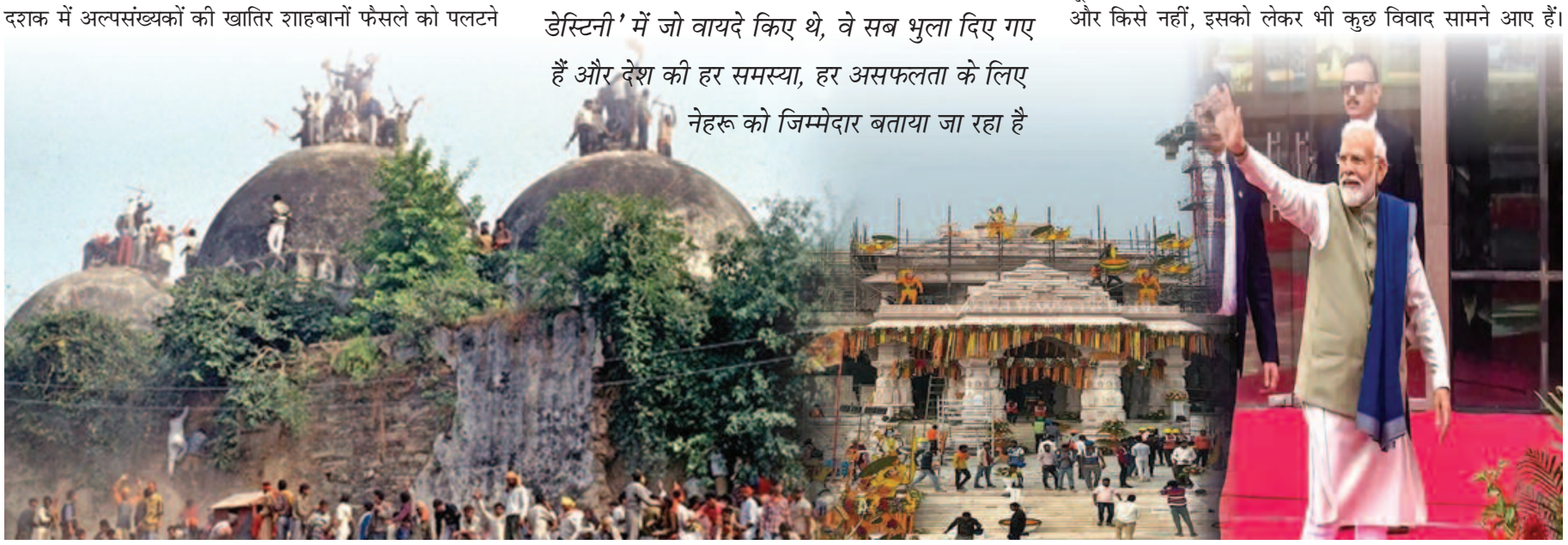

नेहरू के 'आधुनिक भारत के मंदिरों' का निर्माण करने की बजाय, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाने लगे। बाबरी मस्जिद को लेकर खड़ा किया गया विवाद, इसी अभियान का हिस्सा था। सन १९८० में संघ परिवार में एक नए सदस्य का जन्म हुआ। वह सदस्य थी भाजपा। कुछ दिन तक यह नई पार्टी गांधीवादी समाजवाद में आस्था रखने का नाटक करती रही। इसका नेतृत्व नर्म नेता का मुखौटा पहने अटल बिहारी वाजपेयी की हाथ में था। वाजपेयी संघ की विचारधारा में पूर्ण आस्था रखते थे। 'हिंदू तनमन, हिंदू जीवन', उन्होंने अपने बारे में लिखा था। लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई से अपने असली हिंदू राष्ट्रवादी चेहरे को ढंक कर रखा। बाद में उनकी जगह लालकृष्ण आडवाणी ने ले ली। अडवाणी ने 'मंदिर वहीं बनाएंगे' का नारा बुलंद किया।

संघ परिवार लोगों को यह समझाने में सफल रहा कि भगवान राम का जन्म ठीक उसी स्थान पर हुआ था जहां बाबरी मस्जिद थी। मंडल आयोग की रपट के लागू होने से राम रथयात्रा को और ताकत मिली। यात्रा अपने पीछे खून की एक गहरी रेखा छोड़ती गई। सन १९९० के आस-पास, देश के विभिन्न हिस्सों में इस यात्रा के गुजरने के बाद हुई हिंसा में करीब १,८०० लोग मारे गए। लालू प्रसाद यादव द्वारा अडवाणी की गिरफ्तारी के साथ यह यात्रा समाप्त हो गई।

सन १९९२ के छह दिसंबर को चुने हुए कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया। उन्हें बाकायदा इसका प्रशिक्षण दिया गया था और उन्होंने इसकी रिहर्सल भी की थी। जिस समय मस्जिद तोड़ी जा रही थी, मंच पर अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी और उमा भारती भी थे मंच से 'एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो' और 'ये तो केवल झांकी है, काशी, मथुरा बाकी हैं' जैसे नारे लगाए जा रहे थे। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद मुंबई, भोपाल, सूरत और कई अन्य शहरों में भयावह सांप्रदायिक हिंसा हुई और अंततः हमारी न्याय प्रणाली ने हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों के समक्ष समर्पण करते हुए इस मामले का निर्णय 'आस्था' के आधार पर सुना दिया। फैसले में उन लोगों के नाम लिए गए जिन्होंने मस्जिद के विध्वंस का नेतृत्व किया था मगर उन्हें उनके अपराध की कोई सजा नहीं दी गई। न्यायपालिका ने मस्जिद की पूरी जमीन 'हिंदू पक्ष' को दे दी।

अपनी इस सफलता से आल्हादित संघ परिवार ने देश से और विदेशों से भी भारी धनराशि एकत्र की और उससे बना भव्य राममंदिर अब तैयार है। इसका उद्घाटन पूरे हिंदू कर्मकांडों के साथ स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष सरकार के मुखिया के हाथों यह मंदिर जनता के लिए खुलेगा। जब तक बाबरी मस्जिद थी, तब तक वह भाजपा के चुनाव अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। उसके बाद से 'भव्य राममंदिर' का निर्माण पार्टी के चुनाव घोषणापत्रों और वायदों का अहम हिस्सा रहा है। गुजरे सालों में मुसलमान अपने मोहल्लों में सिमट गए हैं, देश का सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है और भाजपा की चुनावी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

वर्तमान स्थिति का सारगर्भित वर्णन लेखक एएम सिंह ने इन शब्दों में किया है: 'सत्ता में आने के बाद से, भाजपा के राजनीतिक आख्यान ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया है और भाजपा सरकार ने इसी दिशा में कई कदम भी उठाए हैं। संविधान के अनुच्छेद ३७० को निष्प्रभावी किया गया और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पारित किया। भारत की नागरिकता को हिंदुत्व के सिद्धांतों के आधार पर पुनर्परिभाषित कर, भाजपा सरकार ने हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के मूल्य के भविष्य और उसकी विरासत को किरच-किरच कर दिया है।' अपने मोहल्लों में सिमटे मुसलमान, समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है।

मंदिर के उद्घाटन के मौके का इस्तेमाल हिंदुओं को गोलबंद करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका और अन्य देशों में अप्रवासी भारतीय इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। देश के भीतर, आरएसएस और उसके परिवार के सदस्य हिंदुओं को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि या तो वे नए मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाएं या उस दिन स्थानीय मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना करें। इस समारोह में किसे आमंत्रित किया गया है और किसे नहीं, इसको लेकर भी कुछ विवाद सामने आए हैं। पहले मंदिर ट्रस्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मुख्य आर्किटेक्ट आडवाणी और उनके नजदीकी सहयोगी मुरलीमनोहर जोशी से कहा कि इन दोनों नेताओं की उम्र और अयोध्या में उस समय जबरदस्त ठंड पड़ने की संभावना के चलते उन्हें कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए। बाद में शायद इस मसले पर पुनर्विचार हुआ और विहिप ने दोनों को आमंत्रित किया।

बाबरी मस्जिद के विविध्वंस ने फिरकापरस्त ताकतों को सत्तासीन किया और अब मंदिर के उद्घाटन का उपयोग ध्रुवीकरण को और गहरा करने और उससे चुनावों में लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए बड़ी संख्या में विशेष रेलगाड़ियों और बसों का इंतजाम हो रहा है।

यह वह समय है जब हमें नेहरू के 'आधुनिक भारत के मंदिरों' की संकल्पना और वैज्ञानिक समझ के विस्तार और विकास के प्रयासों को याद करना चाहिए। इस समय धार्मिकता और अंधश्रद्धा को जबरदस्त बढ़ावा दिया जा रहा है। जब हमनें औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को तोड़ा था, तब हमने यह संकल्प लिया था कि 'अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति' हमारा फोकस होगा। परंतु आज राजनीति अयोध्या के राममंदिर के आसपास घूम रही है और उसके बाद, काशी और मथुरा तो बाकी हैं ही। ऐसे में 'अंतिम व्यक्ति' की किसे चिंता है? नेहरू ने 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' में जो वायदे किये थे, वे सब भुला दिए गए हैं और देश की हर समस्या, हर असफलता के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताया जा रहा है।

(लेखक के ये अपने विचार हैं।)

07 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक के लिए प्रकाशित

संपादक : अपूर्व* कार्यकारी संपादक (विचार) : आदेश भाटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सुनील भारद्वाज, रोविंग एसोसिएट एडिटर : आकाश नागर
उप संपादक : जीवन सिंह टनवाल, जनार्दन कुमार सिंह, मो. रुस्तम, नीतू टीटाण उत्तराखण्ड प्रभारी : दिव्य सिंह रावत, विशेष संवाददाता : कृष्ण कुमार, मुख्य संवाददाता
कुमाऊं : संजय स्वार, संवाददाता : दिनेश पंत, गोपाल बोरा, गढ़वाल संवाददाता : जसपाल नेगी, अली खान, प्रबंधक : अमित कुमार : 9582371321 **प्रधान कार्यालय :** बी-107, सेक्टर-63, नोएडा, फोन : 0120-4330755, फैक्स : 0120-4352397,
उत्तराखण्ड कार्यालय : रोहणी प्लाजा, कॉम्प्लेक्स, 28 दूसरी मंजिल 11 ई, राजपुर रोड, देहरादून, मो. : 09412901406 **कुमाऊं कार्यालय :** प्रथम तल, नंदा इंक्लेव, नरसिंह तल्ला, कमलवागांजा रोड हल्द्वानी-263139, नैनीताल।
* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी। स्वत्वाधिकारी इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसायटी के लिए प्रकाशक, मुद्रक नारायण सिंह राणा द्वारा बी.एफ.एल. इन्फोटेक लि., सी-9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित एवं 3, रोहणी प्लाजा, कॉम्प्लेक्स, 28 दूसरी मंजिल 11 ई, राजपुर रोड, देहरादून से प्रकाशित।

असीमित संभावनाओं-आशंकाओं का वर्ष 2024

अपूर्व
editor@thesundaypost.in

प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई छवि, भाजपा की सांगठनिक क्षमता और उसकी चुनाव मैनेजमेंट रणनीति के आगे पस्त विपक्ष 2024 के आम चुनाव, जो अब मात्र तीन माह दूर है, तक खुद को एकजुट कर भाजपा को कड़ी चुनौती देने में सक्षम होता नहीं प्रतीत होता है। वर्तमान हालातों में भाजपा तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होती दिखाई दे रही है। 2024 में बहुत कुछ ऐसा होगा जो भविष्य में, जब यह वर्ष इतिहास बन चुका होगा, इसे याद रखने लिए, इसकी अलग-अलग कारणों से मीमांसा किए जाने का कारण बनेगा। यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि 2024 लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय सरोकारों की रक्षा करने वाला वर्ष साबित होने जा रहा है या फिर विश्व भर में कट्टर राष्ट्रवाद के नाम पर तानाशाही और मानवीयता के क्षरण के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला वर्ष। जैसा भी होगा, यह तय है कि यह एक सामान्य वर्ष नहीं होगा

२०२४ कोई सामान्य वर्ष नहीं है। यह वर्ष नाना प्रकार की संभावनाओं और आशंकाओं का वर्ष है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष विश्व के कई महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होने तय हैं। इन देशों में भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और ताइवान शामिल हैं। हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस वर्ष की शुरुआत में ही चुनाव होने जा रहे हैं। अमेरिकी चुनावों के नतीजे न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए खास मायने रखते हैं। वर्तमान समय में अमेरिकी राजनीति दो विपरित धुव्रों के बीच पेन्डुलम की भांति झूल रही है। एक तरफ अराजक दक्षिणपंथी नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं तो दूसरी तरफ वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन जिनका बतौर राष्ट्रध्यक्ष कार्यकाल खास उत्साहजनक नहीं रहा है। ट्रंप को चुनाव लड़ने से रोकने के कानूनी प्रयास भी अमेरिकी राजनीति में भारी धुव्रीकरण पैदा कर चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन का कार्यकाल हालांकि ट्रंप के कार्यकाल की बनिस्पत किसी बड़े विवाद का कारण नहीं बना, बाइडन लेकिन आम अमेरिकियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान निकाल पाने में खास सफल नहीं हो पाए। खराब स्वास्थ सेवाओं और सामाजिक, असमानता जैसे मुद्दों से अमेरिकी समाज लगातार दो-चार हो रहा है। बाइडन ऐसे संवेदनशील मुद्दों के मकड़जाल में तो फंसे ही रहे हैं, विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति की छवि को यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध ने भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अमेरिका और उसके साथ चलने वाले पश्चिमी देशों के हितों को बीते ३ वर्षों से लगातार आघात पहुंच रहा है। २०२४ इस दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है। यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे नाटो से जुड़े देशों का अनुमान था कि उनके द्वारा भेजी जा रही सैन्य मदद और यूक्रेन सेना को दी गई युद्ध ट्रेनिंग के नतीजे सुखद रहेंगे और रूस द्वारा कब्जाए गए अपने इलाकों को यूक्रेन वापस कब्जा लेगा। ऐसा लेकिन हुआ नहीं। अमेरिका यूक्रेन के समर्थक देशों की अगुवाई कर रहा है। उसने अरबों डॉलर इस युद्ध में झोंके लेकिन नतीजे उसकी सोच अनुसार नहीं रहे हैं। अब इस युद्ध को लेकर बाइडन की नीति का विरोध होने लगा है और यूक्रेन को ६० अरब डॉलर की सैन्य सहायता के उनके प्रस्ताव को अमेरिकी संसद ने रोक दिया है। यूरोपीय संघ भीतर भी इस युद्ध चलते मतभेद उभरने लगे हैं। इस संघ के कुछ देशों द्वारा यूक्रेन को ५० अरब यूरो बतौर सहायता दिए जाने का प्रस्ताव हंगरी ने अपनी आपत्ति दर्ज करा रोक दिया है। इस बीच रूस लगातार अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में सफल होता नजर आ रहा है उसने अपने वार्षिक बजट का एक तिहाई हिस्सा रक्षा के लिए समर्पित कर यह स्पष्ट करने का काम किया है कि निकट भविष्य में इस युद्ध को समाप्त होना नहीं है। अमेरिका और उसके समर्थक देशों के लिए यह खासी निराशा का कारण बन चुका है। मार्च २०२३ में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पुतिन को युद्ध अपराधों के लिए दोषी करार दे उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। अमेरिका और यूरोपीय संघ को तब लगा था कि अब पुतिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर अछूत बन जाएंगे, ऐसा भी लेकिन हुआ नहीं। राष्ट्रपति पुतिन अंतरराष्ट्रीय अपराधी घोषित किए जाने के बाद भी चीन, सऊदी अरब और यूएई की यात्रा पर गए और उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी वर्चुअली अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इजराइल-गाजा युद्ध भी अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। अरब देश सवाल कर रहे हैं कि यूक्रेन में नागरिकों की हत्या के लिए रूस की निंदा करने वाले देश गाजा में इजराइल द्वारा किए जा रहे युद्ध अपराध पर खामोश क्यों हैं? इस सबके बीच ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बड़ी आशंका बन उभरा है। रूस संग उसकी गहराती दोस्ती २०२४ में कुछ बड़ा गुल खिलाए जाने की तरफ इशारा कर रही है। उत्तर कोरिया भी रूस के नजदीक हो चला है। अफ्रीकी महाद्वीप में भी राजनीति तेजी से बदल रही है। २०२३ में कई अफ्रीकी राष्ट्रों में यूरोप के प्रति असंतोष चरम पर पहुंचा जो २०२४ में गति पकड़ सकता है। यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका भी पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता को कम करता नजर आने लगा है। रूस और चीन के साथ उसके संयुक्त सैन्य अभ्यास इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ताइवान और इंडोनेशिया में भी चुनावों के नतीजे इन देशों में लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाले साबित होंगे।

अपने देश की बात करूं तो २०२४ में ही हमारे यहां भी आम चुनाव होना तय है। इस चुनाव का नतीजा हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला साबित हो सकता हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बड़े वर्ग को आशंका है कि मोदी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाने में सफल रहे तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। इस वर्ग की आशंका के पीछे बीते पौने दस वर्षों के दौरान लोकतंत्र का स्तंभ कहलाए जाने वाले न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायकी और प्रेस की कार्यशैली में आई गंभीर गिरावट का होना है। भाजपा विरोधी राजनीतिक दल एक सुर में आलाप रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों-सीबीआई, ईडी और इंकमटैक्स, के जरिए प्रतिरोध की हर आवाज को कुचलने पर आमदा है। एक संघीय व्यवस्था वाले देश में केंद्र और राज्यों के मध्य बढ़ रहा तनाव भी निश्चित ही स्वास्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। केंद्र द्वारा नामित राज्यपालों का विभिन्न विपक्ष शासित राज्यों की सरकारों संग टकराव इस हद तक जा पहुंचा है कि उच्चतम न्यायालय को बार-बार हस्तक्षेप कर राज्यपालों को सीमा भीतर रहकर काम करने की सलाह देनी पड़ रही है। कई राज्य सरकारों ने सीबीआई के अपने राज्य में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। तमिलनाडु में, जहां ईडी बीते कुछ वर्षों के दौरान खासी सक्रिय रही है, हालात इस स्तर तक जा पहुंचे हैं कि ईडी के राज्य में तैनात सहायक निदेशक को तमिलनाडु पुलिस ने रिश्वतखोरी के एक मामले में रंगे हाथ पकड़ जेल भेज दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में लगभग समूचे विपक्षी सांसदो को निलंबित किया जाना सत्तारूढ़ दल के अहंकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उसकी असहिष्णु प्रवृत्ति को सामने लाता है। यदि प्रधानमंत्री मोदी २०२४ के आम चुनाव जीत तीसरी बार केंद्र सरकार का गठन कर पाने में सफल रहते हैं तो देश में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर पहले से ही आशंकित वर्ग की चिंताओं में इजाफा होना तय है। ऐसों को भय है कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद पूरे देश में धर्म आधारित धुव्रीकरण के प्रयास तेज होंगे जिसका सीधा प्रभाव सामाजिक सौहार्द पर पड़ेगा। रही बात विपक्षी दलों की तो वे केंद्र सरकार पर अलोकतांत्रिक और तानाशाह होने के आरोप तो लगातार लगा रहे हैं, संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शन इत्यादि भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित हो भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार कर पाने में सफल होते हाल-फिलहाल तक नजर नहीं आ पाए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई छवि, भाजपा की सांगठनिक क्षमता और उसकी चुनाव मैनेजमेंट रणनीति के आगे पस्त विपक्ष २०२४ के आम चुनाव, जो अब मात्र तीन माह दूर है, तक खुद को एकजुट कर भाजपा को कड़ी चुनौती देने में सक्षम होता नहीं प्रतीत होता है। वर्तमान हालातों में भाजपा तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होती दिखाई दे रही है। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित ही पूरे आत्मविश्वास के साथ भाजपा सीएए, एनआरसी, कृषि कानूनों में व्यापक संशोधन, समान नागरिक आचार संहिता समेत उन सभी मुद्दों को प्रभावी तौर पर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी जिन मुद्दों को लेकर आमजन का एक वर्ग और विपक्षी दल खिलाफत करते रहे हैं। यदि चुनाव नतीजे भाजपा के मनोकूल नहीं आते हैं और इंडिया गठबंधन सरकार बना पाने में सफल होता है तो राजनीतिक अस्थिरता के दौर की शुरुआत २०२४ में होनी तय है। एक बार फिर से १९९६-१९९८ का वक्त वापस लौट सकता है जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने का खामियाजा बार-बार अल्पकाल की सरकारों का गठन और मध्यावधि चुनावों को कराए जाने बतौर देश ने भुगता था।

२०२४ में बहुत कुछ ऐसा होगा जो भविष्य में, जब यह वर्ष इतिहास बन चुका होगा, इसे याद रखने के लिए, इसकी अलग-अलग कारणों से मीमांसा किए जाने का कारण बनेगा। यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि २०२४ लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय सरोकारों की रक्षा करने वाला वर्ष साबित होने जा रहा है या फिर विश्व भर में कट्टर राष्ट्रवाद के नाम पर तानाशाही और मानवीयता के क्षरण के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला वर्ष। जैसा भी होगा, यह तय है कि यह एक सामान्य वर्ष नहीं होगा।

सरगोशियां

फिर पलटी मारेंगे नीतीश!

लोकसभा चुनाव २०२४ से पहले बिहार की राजनीति गरमा गई है। सियासी गलियारों में इन दिनों यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। हालांकि जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पारित प्रस्तावों से तो यही पता चलता है कि वह फिलहाल एनडीए में जाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। जेडीयू ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या गठबंधन के संयोजक बनने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन आम चुनाव से करीब तीन महीने पहले जेडीयू ने जो बड़ा फैसला पार्टी अध्यक्ष रहे ललन सिंह का इस्तीफा और फिर नीतीश कुमार को कमान दी गई है उसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलते हुए भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं। इसकी वजह यह मानी जा रही है कि ललन सिंह अंदरखाने राजद के साथ डील करना चाहते थे और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। इन कयासों को पार्टी नेता केसी त्यागी के बयान ने और बढ़ा दिया है। बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी त्यागी ने कहा कि भाजपा हमारी दुश्मन नहीं है। राजनीति में कोई भी दुश्मन नहीं होता। इस तरह केसी त्यागी ने खुलकर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक हिंट जरूर छोड़ गए कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ भी हो सकता है।

एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे

आगामी आम चुनाव की पृष्ठभूमि में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हलचल देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र की सबसे चर्चित पार्टी और मराठी लोगों के मुद्दों के लिए लड़ने वाले प्रभावी नेता के रूप में जाने जाने वाले 'मनसे' अध्यक्ष राज ठाकरे इस चुनाव में किसका पक्ष लेंगे? राजठाकरे ने हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। इसके बाद सामने आया है कि इन नेताओं के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि महाराष्ट्र में राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न कैसे मनाया जाए। इस बीच सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं की ओर से परोक्ष रूप से राज ठाकरे को अपने साथ आने की पेशकश करने वाले बयान भी आने लगे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे की पार्टी के दो बड़े नेताओं ने राज ठाकरे को लेकर अहम बयान दिया है। इन नेताओं ने राज ठाकरे और मुख्यमंत्री शिंदे की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम राज ठाकरे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी जो इस समय राज्य और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, के बड़े नेता गिरीश महाजन ने राज ठाकरे को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने राज ठाकरे को समान विचारधारा वाला बता कहा कि अगर वे आ रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आलोचना वहीं करनी चाहिए जहां गलतियां हों, हम समान विचारधारा वाले हैं। इसके बाद से चर्चा है कि राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राज ठाकरे एनडीए के लिए अहम हैं क्योंकि राज ठाकरे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले नेता हैं और युवाओं में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। अगर राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर एनडीए में शामिल होते हैं तो सत्ताधारी पार्टियों की ताकत बढ़ जाएगी।

सहयोगियों ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता

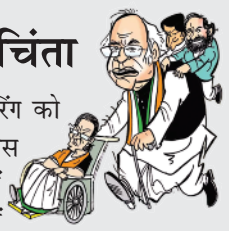

'इंडिया गठबंधन' में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने घटक दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर उन्हें टटोलने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस पर सहयोगी दलों ने दबाव बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। एक ओर जहां जेडीयू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार के रूप में पेश कर कहा कि भारतीय राजनीति में केवल कुछ ही नेता हैं जो उनके जैसे अनुभवी हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया कि इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वे गठबंधन को सफल बनाने के लिए बड़ा दिल दिखाए। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि वह महाराष्ट्र की ४८ लोकसभा सीटों में से २३ पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के साथ उसकी बातचीत शून्य से शुरू होगी क्योंकि २०१९ के लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में भगवा पार्टी ने कोई भी सीट नहीं जीती है। इन दोनों पार्टियों के बयानों से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी राज्य में भाजपा से मुकाबला करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि देशभर में बीजेपी का मुकाबला इंडिया से होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व टीएमसी करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहले से पंजाब और दिल्ली में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा ऐसा बयान दिया गया है, जिससे 'इंडिया गठबंधन' से उनका मोहभंग होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव २०२४ को लेकर दावा किया कि चुनाव में 'पीडीए' का फॉर्मूला ही एनडीए को हरा सकता है। अपनी पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार भी इंडिया गठबंधन का जिक्र नहीं किया और न ही उसके बारे में कोई राय रखी। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अखिलेश अब 'इंडिया गठबंधन' से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन के सहयोगी दलों के इन बयानों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

नागपुर से क्यों भरी हुंकार

आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस की रैली

दि संडे पोस्ट डेस्क

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने अपने १३९ वें स्थापना दिवस के दिन रैली के लिए नागपुर को चुना। ये शहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का गढ़ कहा जाता है। नागपुर में कांग्रेस की इस रैली को लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि हाल ही में हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में मिली हार के बाद भी पार्टी का मनोबल गिरा नहीं है और वो २०२४ के चुनाव के लिए पूरी तैयार हैं।

नागपुर में हुई कांग्रेस की ये रैली पूरे देश में सुर्खियां बन गई, क्योंकि आरएसएस के गढ़ से कांग्रेस ने हुंकार भरी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर नागपुर से ही कांग्रेस ने आगामी चुनाव का शंखनाद क्यों किया? यहां तक कि जिस मैदान में कांग्रेस की इस मेगा रैली का आयोजन किया गया उस ग्राउंड का नाम भारत जोड़ो ग्राउंड रखा गया। खास बात ये है कि महाराष्ट्र के जिस मैदान में कांग्रेस ने अपने१३९ वें स्थापना दिवस के दिन लाखों लोगों की भीड़ जुटाई, वहां से आरएसएस का मुख्यालय सिर्फ ६५ किलोमीटर दूर है। लोगों के मन में सवाल है कि राहुल गांधी ने रैली के लिए आखिर नागपुर को ही क्यों चुना? क्या राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं वो आरएसएस के गढ़ में घुसकर चुनौती देंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नागपुर किसी और का नहीं कांग्रेस का गढ़ है। नागपुर में सिर्फ आरएसएस का मुख्यालय ही नहीं है। इस शहर में ऐतिहासिक स्थल दीक्षाभूमि भी है।

दीक्षाभूमि में ही डॉ बीआर आंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कांग्रेस संदेश दे रही है कि वो वहां से चोट करना चाहती है जहां से बीजेपी के लिए एजेंडा तय होता है और बीजेपी इसका अपने ही अंदाज में जवाब दे रही है। राहुल गांधी का नागपुर से चुनावी रैली कितनी लंबी लकीर खींच पाती है इसके लिए तो काफी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नागपुर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करके कांग्रेस कैडर का मनोबल बढ़ाने में वो कामयाब जरूर हुए हैं। नागपुर को कांग्रेस अपना गढ़ क्यों बता रही है, उसे समझने की जरूरत है। १९५२ से अब तक नागपुर लोकसभा सीट पर १८ बार चुनाव हुए हैं और इनमें १३ बार कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी ने तीन बार नागपुर लोकसभा सीट पर चुनाव जीता है।

वर्ष २०१४ से लगातार दो बार नितिन गडकरी के नागपुर से जीत दर्ज करने के बाद नागपुर बीजेपी का गढ़ माने जाना लगा। हालांकि वो शहर नागपुर ही था जब इमरजेंसी के ठीक बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रैली की थी और विदर्भ रीजन की सारी सीटें कांग्रेस ने जीत ली थीं। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में नागपुर से २०२४ के चुनावी कैंपेन का आगाज करने के पीछे सिर्फ आरएसएस फैक्टर नहीं है। कांग्रेस महाराष्ट्र के उस हिस्से को और मजबूत करना चाहती है जो उसके लिए बड़ी ताकत साबित होता रहा है। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। इसलिए महाराष्ट्र को कांग्रेस और मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ पूरे देश में इस वक्त २२ जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की चर्चा है। रामलला की मूर्ति कैसी होगी, कार्यक्रम कितना भव्य होगा, रामलला का दरबार कैसा होगा? राम भक्त इन सवालों के जवाब के लिए २२ तारीख का इंतजार कर रहे हैं और २०२४ के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसे भुना रही है।

वह देश को बता रही है कि मंदिर को लेकर किया वायदा बीजेपी ने पूरा कर दिया है। बीजेपी इसे आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना के तौर पर पेश करने का प्लान बना रही है। वहीं राम मंदिर की काट में राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है और खास बात ये है कि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा राम मंदिर समारोह से ठीक पहले शुरू करने जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि करीब एक साल पहले राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' की थी। राहुल गांधी ने इसका आगाज दक्षिण से किया था और कन्याकुमारी से चलकर १३६ दिन बाद कश्मीर तक का सफर तय किया था। इस यात्रा को राहुल के राजनीतिक करियर में एक बड़ी उपबल्धि के तौर पर गिना गया और अब ठीक एक साल बाद राहुल ने लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा पार्ट टू के तौर पर भारत न्याय यात्रा का ऐलान किया है। जो १४ जनवरी को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से शुरू होगी और ६७ दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए लगभग ६२०० किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। राहुल की भारत न्याय यात्रा १४ राज्य और ८५ जिलों से होते हुए गुजरेगी। ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और आखिर में महाराष्ट्र पहुंचेगी।

अब क्या करेंगे सोरेन?

ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने सातवें समन में बयान दर्ज कराने के लिए इस बार यह सुविधा दी है कि वे खुद समय, तिथि और जगह बताएं। ईडी के अधिकारी उनसे उनके बताए स्थान समय और तिथि को आकर पूछताछ करेंगे। ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी नोटिस में यह भी लिखा है कि वे जान-बूझकर इस मामले की जांच से बच रहे हैं और ईडी की ओर से जारी किए गए समन की अवहेलना कर रहे हैं। अब ईडी ने सातवां समन जारी कर कहा कि अगर अब जान-बूझकर समन की अवहेलना की जाती है तो ईडी के पास इस संबंध में पीएमएलए एक्ट की धारा के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं अब क्या करेंगे सीएम सोरेन? ईडी के अनुसार सात दिनों के भीतर पूछताछ कर लेनी है। ईडी ने यह भी लिखा है कि एजेंसी का कोई भी समन दुर्भावनापूर्ण या राजनीति से प्रेरित नहीं है। ईडी ने हेमंत सोरेन को भेजे नोटिस में यह भी लिखा है कि बड़गाई अंचल के गिरफ्तार अंचल उपनिरीक्षक भानू प्रताप प्रसाद के घर से छापेमारी के दौरान ईडी को जमीन के कई अहम दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद ईडी ने उक्त मामले में ईसीआईआर (आरएनजेडओ २५-२३) दर्ज किया था जिसका अनुसंधान ईडी कर रहा है। इसी मामले में ईडी पूछताछ के लिए इससे पहले हेमंत सोरेन को छह समन जारी कर चुका है और यह उसका सातवां समन है। पूर्व में भेजे गए छह समन में प्रत्येक समन को सोरेन ने दुर्भावना से प्रेरित बताया था। सीएम ने ईडी पर केंद्र के इशारे पर काम करने व लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया था।

उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों से बचाना, उनको उनके उत्पाद की सही कीमत दिलाना, ग्राहकों को उच्च श्रेणी का दूध पिलाना तथा अन्य डेयरी से जुड़ी वस्तुओं को उपलब्ध कराने के पवित्र उद्देश्य से किया जरूर गया था लेकिन बीते 22 वर्षों के दौरान ये उद्देश्य कहीं हवा हो गए हैं। इस फेडरेशन में भारी भ्रष्टाचार पनप चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि राज्य की जनता को 'आंचल' ब्रांड के तहत बेचे जा रहे दूध में बड़ी मात्रा में मिलावट किए जाने चलते दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। हैरानी की बात यह कि राज्य सरकार सभी तथ्यों से भलीभांति परिचित होने के बावजूद फेडरेशन के भ्रष्ट कर्ताधर्ताओं पर कोई कार्रवाई करने से बच रही है। इस कहानी के दो पहलू हैं। पहला दूध की गुणवत्ता का है जिसको लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मय प्रमाण डेयरी फेडरेशन द्वारा खरीदे जा रहे और विक्रय किए जा रहे दूध को स्वास्थ के लिए हानिकारक बताया गया है। इस याचिका में फेडरेशन के प्रशासक और नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश बोरा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बोरा सत्तारूढ़ भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता भी हैं। फेडरेशन में हो रहे आर्थिक भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम भाजपा के ही एक नेता ने किया है जिनकी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश मई 2023 में दिए थे। जांच रिपोर्ट में फेडरेशन से जुड़े नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, लालकुआं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सही पाया गया है लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई न किया जाना डेयरी विकास मंत्रालय की कार्यशैली और सत्यनिष्ठा को संदेह के घेरे में ला रहा है

दागदार हुआ 'आंचल'

फोटो : यूसीडीएफ पोर्टल से साभार

आंचल डेयरी के प्रोडक्ट लॉन्च के अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा संग मुकेश बोरा (बाएं)

आकाश नागर
akash@thesundaypostèin

पटकथा

यह कहानी है उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की। इस को-ऑपरेटिव संस्था के जरिए प्रदेश के १३ में से ११ जिलों में दूध उत्पादकों से दूध खरीदा जाता है और इसे संस्था के पंजीकृत ब्रांड 'आंचल' के नाम से प्रदेश भर में बेचा जाता है। राज्य गठन के बाद, वर्ष २००१ में, संस्था का गठन इस पवित्र उद्देश्य से किया गया था कि दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का उचित मूल्य मिल सके और उच्च गुणवत्ता का दूध तथा अन्य डेयरी की वस्तुएं आमजन को उपलब्ध कराई जा सकें। संस्था के अंतर्गत राज्य के ११ जिलों में दुग्ध उत्पादक को-ऑपरेटिव संस्थाएं कार्य करती हैं जिनके जरिए लगभग १.८५ लाख लीटर दूध प्रति दिन खरीदा जाता है और १.४८ लाख लीटर दूध की बिक्री होती है। इस को-ऑपरेटिव फेडरेशन का गठन उत्तराखण्ड के दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों से बचाना, उनको उनके उत्पाद की सही कीमत दिलाना तथा ग्राहकों को उच्च श्रेणी का दूध तथा अन्य डेयरी से जुड़ी वस्तुओं को उपलब्ध कराने के पवित्र उद्देश्य से किया जरूर गया था लेकिन बीते २२ वर्षों के दौरान ये उद्देश्य कहीं हवा हो गए हैं और इस फेडरेशन में भारी भ्रष्टाचार पनप चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि राज्य की जनता को 'आंचल' ब्रांड के तहत बेचे जा रहे दूध में बड़ी मात्रा में मिलावट किए जाने चलते दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। हैरानी की बात यह कि राज्य सरकार सभी तथ्यों से भलीभांति परिचित होने के बावजूद फेडरेशन के भ्रष्ट कर्ता-धर्ताओं पर कोई कार्यवाई करने से बच रही है। इस कहानी के दो पहलू हैं। पहला दूध की गुणवत्ता का है जिसको लेकर बिंदुखत्ता, लालकुआं के निवासी नरेंद्र सिंह कार्की ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें मय प्रमाण डेयरी फेडरेशन द्वारा खरीदे जा रहे और विक्रय किए जा रहे दूध को स्वास्थ के लिए हानिकारक बताया गया है। इस याचिका में इस फेडरेशन के वर्तमान प्रशासक मुकेश बोरा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दूसरा पहलू फेडरेशन में हो रहे आर्थिक भ्रष्टाचार की बाबत है। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम हल्द्वानी निवासी हरीश चन्द्र आर्या ने किया है जिनकी शिकायत पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमीशनर को जांच के आदेश मई २०२३ में दिए थे।

'दि संडे पोस्ट' के पास उपलब्ध जानकारी अनुसार अक्टूबर, २०२३ में कुमाऊं कमीशनर दीपक रावत ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी। रिपोर्ट में फेडरेशन से जुड़े नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, लालकुआं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सही पाया गया है लेकिन कई माह बीतने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई न किया जाना राज्य सरकार, विशेषकर डेयरी विकास मंत्रालय, की कार्यशैली और सत्य निष्ठा को संदेह के घेरे में ला रहा है।

पड़ताल

भ्रष्टाचारियों पर कराउंगा मुकदमा दर्ज

नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं में वित्तीय अनियमितताओं का भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है। मैलामाइन एल्कोहल मिलाकर दुध को आम जनता को पिलाया गया। मानव जीवन से खिलवाड़ किया गया। कुमाऊं कमिश्नर की जांच रिपोर्ट मैलामाइन एल्कोहल की पुष्टि अभिलेखों सहित मा. उच्च न्यायालय में सप्लीमेंट्री अरजेंसी दाखिल कर जल्द रिट संख्या १८६, में ठोस पैरवी कर भ्रष्ट अधिकारियों, विभागीय मंत्री, दुग्ध संघ, तत्कालीन अध्यक्ष (यूसीडीएफ) और चेयरमैन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। जब तक घोटालों की रिकवरी न हो और भ्रष्ट अधिकारी निलंबित न हो तब तक चैन से नहीं बैठूंगा।

भुवन चन्द्र पोखरियाल, याचिकाकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता

अनसुलझे सवाल

1. अगर मुकेश बोरा ने दुग्ध उत्पादन नहीं किया तो वह दुग्ध उत्पादक कैसे बने? और दुग्ध उत्पादक नहीं थे तो नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष कैसे बन गए?
2. कागजों में दूध मुकेश बोरा ने बेचा और बैंक खातों में उसी दूध का भुगतान दीपा देवी पत्नी इंदल सिंह के नाम कैसे चढ़ गया?
3. जांच कमेटी के समक्ष दुग्ध समिति च्यूरीगाड़ के पर्यवेक्षक उमेश यादव ने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी है जिसमें उन्होंने दीपा देवी के स्थान पर मुकेश बोरा की एंट्री की पुष्टि की है। दीपा देवी के दुग्ध बिक्री की एंट्री मुकेश बोरा के नाम दिखाकर मुकेश बोरा को फर्जी तरीके से दुग्ध उत्पादक बना डाला तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
4. जांच कमेटी में संविदाकर्मी होने के चलते जांच कमेटी की रिपोर्ट रद्द की गई और दूसरी जांच रिपोर्ट में मुकेश बोरा को क्लीनचिट दे दी गई लेकिन दुग्ध समिति च्यूरीगाड़ के पर्यवेक्षक उमेश यादव ने जो सच उजागर किया उसे क्यों दबा दिया गया?
5. उत्तर प्रदेश के बदायूं की नीलकंठ डेयरी का अक्टूबर 2020 से जनवरी 2022 तक लाखों लीटर गुणवत्ताविहीन दुग्ध खरीदा गया। इस दूध के सैंपल भी फेल हुए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह दूध मेथिलीन ब्लू डाईड रिडक्शन टेस्ट (एमबीडीआरटी) और क्लाट ऑन बायलिंग के मानकों पर खरा नहीं उतरा। अल्कोहल टेस्ट में भी आंचल का दूध पाउडर बनाने लायक नहीं पाया गया था। बावजूद इसके खराब क्वालिटी का दूध क्यों खरीदा जाता रहा? लाखों लीटर दूध के सैंपल फेल हो जाने के बाद भी उक्त डेयरी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
6. जांच रिपोर्ट में दूध की गुणवत्ता खराब पाए जाने के बाद भी लाखों लोगों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता रहा, इस डेयरी के संचालकों को किसका संरक्षण मिलता रहा?
7. गुणवत्ताविहीन दूध पीने से लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर कितना हानिकारक प्रभाव पड़ा, इस दूध के पीने से उनको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हुई है। इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई?
8. नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

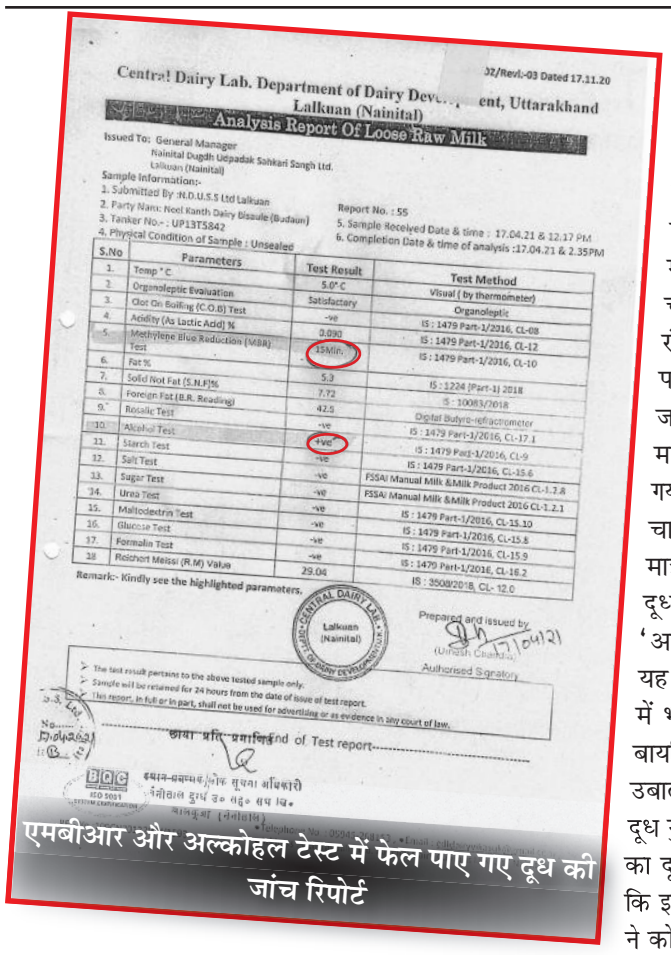

Central Dairy Lab. Department of Dairy Development, Uttarakhand
Lalkuan (Nainital)
Analysis Report Of Loose Raw Milk

Issued To: General Manager
Nainital Dugdh Udpadak Sahkari Sangh Ltd.
Lalkuan (Nainital)

Sample Information:-
1. Submitted By :N.D.U.S.S Ltd Lalkuan
2. Party Nam: Neel Kanth Dairy Bisaule (Budaun)
3. Tanker No.- : UP13T5842
4. Physical Condition of Sample : Unsealed

Report No. : 55
5. Sample Received Date & time : 17.04.21 & 12.17 PM
6. Completion Date & time of analysis :17.04.21 & 2.35PM

S.No	Parameters	Test Result	Test Method
1.	Temp ° C	5.0° C	Visual (by thermometer)
2.	Organoleptic Evaluation	Satisfactory	Organoleptic
3.	Clot On Boiling (C.O.B) Test	-ve	IS : 1479 Part-1/2016, CL-08
4.	Acidity (As Lactic Acid) %	0.090	IS : 1479 Part-1/2016, CL-12
5.	Methylene Blue Reduction (MBR) Test	15Min.	IS : 1479 Part-1/2016, CL-10
6.	Fat %	5.3	IS : 1224 (Part-1) 2018
7.	Solid Not Fat (S.N.F)%	7.72	IS : 10083/2018
8.	Foreign Fat (B.R. Reading)	42.5	Digital Butyro-refractometer
9.	Rosalic Test	-ve	IS : 1479 Part-1/2016, CL-17.1
10.	Alcohol Test	+ve	IS : 1479 Part-1/2016, CL-9
11.	Starch Test	-ve	IS : 1479 Part-1/2016, CL-15.6
12.	Salt Test	-ve	FSSAI Manual Milk &Milk Product 2016 CL-1.2.8
13.	Sugar Test	-ve	FSSAI Manual Milk &Milk Product 2016 CL-1.2.1
14.	Urea Test	-ve	IS : 1479 Part-1/2016, CL-15.10
15.	Maltodextrin Test	-ve	IS : 1479 Part-1/2016, CL-15.8
16.	Glucose Test	-ve	IS : 1479 Part-1/2016, CL-15.9
17.	Formalin Test	-ve	IS : 1479 Part-1/2016, CL-16.2
18	Reichert Meissi (R.M) Value	29.04	IS : 3508/2018, CL- 12.0

Remark:- Kindly see the highlighted parameters.

Prepared and issued by
Authorised Signatory

The test result pertains to the above tested sample only.
Sample will be retained for 24 hours from the date of issue of test report.
This report, in full or in part, shall not be used for advertising or as evidence in any court of law.

End of Test report

एमबीआर और अल्कोहल टेस्ट में फेल पाए गए दूध की जांच रिपोर्ट

हल्द्वानी स्थित इस प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह दूध मेथिलीन ब्लू डाइड रिडक्शन टेस्ट (एमबीडीआरटी) के मानकों में खरा नहीं उतरा। इस टेस्ट के जरिए कच्चे दूध की सूक्ष्मजीव विज्ञानी गुणवत्ता (माइक्रो बायोलॉजिकल क्वालिटी) का पता लगाया जाता है। यह परीक्षण इस तथ्य पर आधारित है कि जब दूध में मौजूद ऑक्सीजन माइक्रोबायोलॉजिकल गतिविधियों के चलते समाप्त हो जाती है तो दूध में मिलाया गया नीला रंग फीका पड़ जाता है। जितनी जल्दी नीला रंग फीका पड़ने लगेगा, दूध की गुणवत्ता उतनी ही खराब मानी जाएगी। उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मानकों अनुसार एक ठीक क्वालिटी के दूध में मिलाया गया नीला रंग कम से कम ३० मिनट तक फीका नहीं पड़ना चाहिए। नीलकंठ डेयरी से खरीदे गए दूध में लेकिन यह रंग मात्र ४ से १६ मिनट के बीच ही फीका पड़ गया था। इस दूध पर नियमानुसार दो अन्य टेस्ट भी किए गए थे। 'अल्कोहल टेस्ट' के जरिए यह पता लगाया गया था कि क्या यह दूध पाउडर बनाने इत्यादि के योग्य है या नहीं। इस टेस्ट में भी दूध खरा नहीं उतरा था। एक अन्य टेस्ट 'क्लाट ऑन बायलिंग' के जरिए पता लगाया जाता है कि क्या इस दूध को उबालने के दौरान थक्के तो नहीं बनते हैं। यदि ऐसा होता है तो दूध गुणवत्ता के मानकोंनुसार नहीं माना जाता है। नीलकंठ डेयरी का दूध इस टेस्ट में भी खरा नहीं उतरा था। हैरानी की बात है कि इस डेयरी के खिलाफ नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने कोई भी कार्रवाई नहीं की।

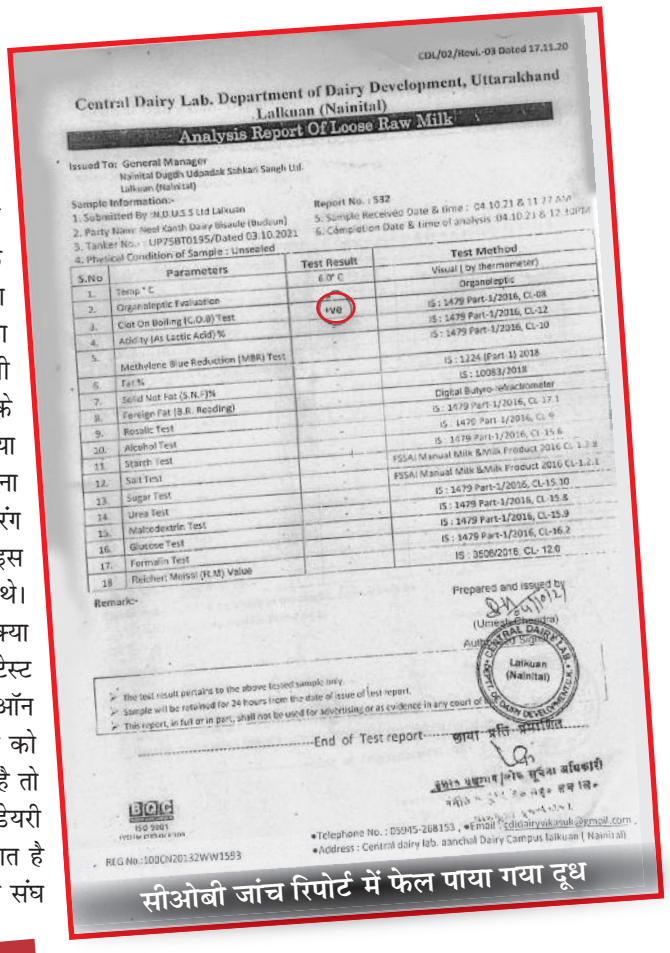

Central Dairy Lab. Department of Dairy Development, Uttarakhand
Lalkuan (Nainital)
Analysis Report Of Loose Raw Milk

Issued To: General Manager
Nainital Dugdh Udpadak Sahkari Sangh Ltd.
Lalkuan (Nainital)

Sample Information:-
1. Submitted By :N.D.U.S.S Ltd Lalkuan
2. Party Nam: Neel Kanth Dairy Bisaule (Budaun)
3. Tanker No.- : UP75BT0195/Dated 03.10.2021
4. Physical Condition of Sample : Unsealed

Report No. : 532
5. Sample Received Date & time : 04.10.21 & 11.22 AM
6. Completion Date & time of analysis :04.10.21 & 12.10PM

S.No	Parameters	Test Result	Test Method
1.	Temp ° C	6.0° C	Visual (by thermometer)
2.	Organoleptic Evaluation		Organoleptic
3.	Clot On Boiling (C.O.B) Test	+ve	IS : 1479 Part-1/2016, CL-08
4.	Acidity (As Lactic Acid) %		IS : 1479 Part-1/2016, CL-12
5.	Methylene Blue Reduction (MBR) Test		IS : 1479 Part-1/2016, CL-10
6.	Fat %		IS : 1224 (Part-1) 2018
7.	Solid Not Fat (S.N.F)%		IS : 10083/2018
8.	Foreign Fat (B.R. Reading)		Digital Butyro-refractometer
9.	Rosalic Test		IS : 1479 Part-1/2016, CL-17.1
10.	Alcohol Test		IS : 1479 Part-1/2016, CL-9
11.	Starch Test		IS : 1479 Part-1/2016, CL-15.6
12.	Salt Test		FSSAI Manual Milk &Milk Product 2016 CL-1.2.8
13.	Sugar Test		FSSAI Manual Milk &Milk Product 2016 CL-1.2.1
14.	Urea Test		IS : 1479 Part-1/2016, CL-15.10
15.	Maltodextrin Test		IS : 1479 Part-1/2016, CL-15.8
16.	Glucose Test		IS : 1479 Part-1/2016, CL-15.9
17.	Formalin Test		IS : 1479 Part-1/2016, CL-16.2
18	Reichert Meissi (R.M) Value		IS : 3508/2018, CL- 12.0

Remark:-

Prepared and issued by
Authorised Signatory

The test result pertains to the above tested sample only.
Sample will be retained for 24 hours from the date of issue of test report.
This report, in full or in part, shall not be used for advertising or as evidence in any court of law.

End of Test report

REG.No.:100CN20132WW1593

सीओबी जांच रिपोर्ट में फेल पाया गया दूध

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में दुग्ध उत्पादकों की शीर्ष संस्था उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रशासक तथा नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के निवर्तमान अध्यक्ष एक ही महानुभाव मुकेश बोरा हैं जो सत्तारूढ़ भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता हैं।

'आंचल' दूध की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल

नरेंद्र सिंह कार्की द्वारा दायर जनहित याचिका अनुसार नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा २३ अक्टूबर, २०२० से १७ जनवरी, २०२२ तक बदायूं उत्तर प्रदेश की नीलकंठ डेयरी से कई लाख लीटर दूध की खरीद की गई थी। इस दूध के सैंपल की जांच सेंट्रल डेयरी लैब द्वारा किए जाने पर यह भयावह सच सामने आया कि इस लाखों लीटर दूध की गुणवत्ता बेहद खराब थी। उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की मंगल पड़ाव,

बात अपनी-अपनी

आप जिस मामले की बात कर रहे हैं उसकी जांच तत्कालीन विभागीय मंत्री धन सिंह रावत जी के कार्यकाल में हुई थी। तब जांच करने वाले अधिकारी संविदा कर्मी थे। बायलाज के अनुसार संविदा कर्मी एक चैयरमेन की जांच नहीं कर सकता है। इसी के साथ यह भी हुआ था कि जांच सक्षम अधिकारी के पास पहुंचने से पहले ही वह आरटीआई में दे दी गई थी। इसके बाद उस जांच को निरस्त करते हुए विभागीय डॉयरेक्टर से एक और जांच कराई गई थी जिसमें मुकेश बोरा को क्लीन चिट दे दी गई। आप कमिश्नर दीपक रावत जी की जिस जांच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वह मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही कराई गई है वह जांच रिपोर्ट मेरे पास नहीं पहुंची है। क्योंकि सीएम साहब ने जांच कराई है तो वह उनके पास ही उसकी रिपोर्ट भी होगी। इसी से संबंधित एक केस माननीय न्यायालय में भी चल रहा है इसलिए मैं ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा।

सौरभ बहुगुणा, दुग्ध डेयरी विकास मंत्री

कुछ ब्लैकमेलर हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं यह उनकी साजिश है क्योंकि मेरा चुनाव चल रहा है तो वह मेरी छवि को खराब करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं आज से नहीं १९९४ से दुग्ध संघ का सदस्य रहा हूं। मुझे केंद्र सरकार द्वारा दुग्ध संघ में डेवन्पमेंट के लिए स्टेट का पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर आपने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। आपको नोटिस भेजूंगा और आप पर मानहानि का केस करूंगा।

मुकेश बोरा, निवर्तमान अध्यक्ष दुग्ध संघ एवं प्रशासक, उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन

यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, कमिश्नर दीपक रावत की रिपोर्ट हमारे पास नहीं पहुंची है।

डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, डेयरी सचिव

मैं इस मामले में कुछ भी कह पाने में सक्षम नहीं हूं।

जयदीप अरोड़ा, प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन

इस प्रकरण में हमारे द्वारा कोई कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित नहीं है।

संजय खेतवाल, डॉयरेक्टर दुग्ध संघ नैनीताल

पड़ताल

मुकेश बोरा पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप

नीलकंठ डेयरी, बदायूं, उत्तर प्रदेश से घटिया गुणवत्ता वाला दूध खरीदने का काम नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा किया गया था। २०१८ में भाजपा नेता मुकेश बोरा इस संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। वर्तमान में बोरा इस संघ के साथ-साथ राज्य की शीर्ष दुग्ध फेडरेशन उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के भी प्रशासक हैं। २०१८ में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चुनावों में बोरा ने खुद को दुग्ध उत्पादक बताया था। गौरतलब है कि दुग्ध संघ के चुनाव नियमानुसार केवल दुग्ध उत्पादक ही लड़ सकते हैं। बोरा ने खुद को नैनीताल के धारी तहसील के गांव च्यूरीगाड़ की दुग्ध उत्पादक संस्था का स्वयं को सदस्य बताते हुए यह चुनाव लड़ा और निर्विरोध जीता था। 'दि संडे पोस्ट' के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मुकेश बोरा न तो दुग्ध उत्पादक थे और न ही उन्होंने कभी च्यूरीगाड़ दुग्ध उत्पादक संस्था को दूध बेचा था।

नियमानुसार किसी भी डॉयरेक्टर या चैयरमेन को दुग्ध समिति का सदस्य होना जरूरी है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि साल में कम से कम १८० दिन उनका दूध डेयरी में गया हो। इसी के साथ यह भी शर्त है कि कम से कम ३२० लीटर दूध उनके द्वारा डेयरी में दिया गया हो। इन दोनों शर्तों को पूरा करने के बाद ही वह व्यक्ति डेयरी का सदस्य अर्थात दुग्ध उत्पादक माना जाएगा। इसके बाद ही वह डेयरी का प्रतिनिधि डॉयरेक्टर और चैयरमेन तक बन सकता है। आरोप है कि दुग्ध संघ का चुनाव लड़ने के लिए मुकेश बोरा ने दुग्ध संघ के कर्मचारियों संग मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे। अक्टूबर, २०२० में एक शिकायती पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय से इस विषयक जांच कराए जाने के निर्देश नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को दिए गए थे। संघ ने तीन अधिकारियों की एक जांच कमेटी को यह जिम्मा सौंपा। जांच कमेटी ने मुकेश बोरा पर फर्जीवाड़ा कर खुद को दुग्ध उत्पादक बताने और च्यूरीगाड़ दुग्ध उत्पादक समिति को दूध बेचने के नकली दस्तावेज बनाने का आरोप सही पाया। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट अनुसार मुकेश बोरा ने दुग्ध समिति च्यूरीगाड़ के क्षेत्र पर्यवेक्षक उमेश यादव के साथ मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। उमेश यादव ने इस दुग्ध समिति की सदस्य श्रीमति दीपा देवी द्वारा समिति को बेचे गए दूध की एंट्री मुकेश सिंह बोरा के नाम से दर्शा मुकेश को दुग्ध उत्पादक बना डाला था।

जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ''दुग्ध समिति च्यूरीगाड़ के क्षेत्र पर्यवेक्षक श्री उमेश यादव द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया है कि वर्ष २०१८-१९-२० में समिति सचिव श्री इंदल सिंह द्वारा समिति सदस्या श्रीमती दीपा देवी जो श्री इंदल सिंह की पत्नी है। उनका दूध समिति अभिलेखों में श्री मुकेश सिंह बोरा पुत्र श्री कुशल सिंह के नाम अंकित किया गया है तथा भुगतान बैंक खातों में स्वयं श्रीमती दीपा देवी पत्नी श्री इंदल सिंह के नाम पर ही लिया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री मुकेश सिंह बोरा को दुग्ध मूल्य, दुग्ध प्रोत्साहन राशि, दुग्ध मूल्य अंतर व बोनस की धनराशि का भुगतान होने का उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा वर्ष २०१८-१९ व वर्ष २०१९-२० में दुग्ध समिति च्यूरीगाड़ में दुग्ध आपूर्ति किया जाना संदिग्ध है।''

इस जांच कमेटी के समक्ष उमेश यादव ने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी है। इतनी स्पष्ट जांच रिपोर्ट के बावजूद मुकेश बोरा के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना प्रदेश सरकार पर, विशेषकर डेयरी विकास मंत्रालय पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

उपसंहार

देवभूमि में बीते सात बरसों से डबल इंजन की सरकार है जिसका दावा है कि राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कर वर्ष २०२५ तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जमीनी हकीकत लेकिन इस दावे की पुष्टि करती नजर नहीं आ रही है। राज्य की शीर्ष दुग्ध उत्पादक संस्था के अध्यक्ष पद पर एक गैर दुग्ध व्यवसायी का काबिज होना इस सहकारी संस्था की नियमावली के खिलाफ तो है ही, फर्जीवाड़े के आरोपों की पुष्टि के बावजूद इस व्यक्ति का नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का अध्यक्ष बन जाना और वर्ष २०२२ में राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक संस्था उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का प्रशासक बन जाना समूची व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है।

पढ़िए अगले अंक में नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की जांच में इन आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद राज्य सरकार की हैरतनाक चुप्पी का सच।

नववर्ष 2024 की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

दिनेश गुरुरानी

राज्य आंदोलनकारी

आइए, एक पौधा धरती के नाम रोपित व पोषित करें

मो. : 8650002538, 9412908530

अतिक्रमण से त्रस्त, अधिकारी मस्त

उत्थान मंच के समीप सुशीला तिवारी अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क को घेरकर भवन स्वामियों द्वारा किया गया अतिक्रमण

राज्य के प्रमुख शहरों में शुमार हल्द्वानी वर्तमान में चौतरफा अतिक्रमण का शिकार हो चला है। हालात इतने विकट हैं कि शहर की मुख्य सड़क नैनीताल रोड तक पर अतिक्रमित कर दिया गया है। यहां से निकलने वाले एक नाले पर किया गया अतिक्रमण हटाने में शहर का प्रशासनिक अमला पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। इस अतिक्रमण चलते बरसात के दिनों में यह मुख्य सड़क स्वयं नाले में तब्दील हो जाती है। हीरानगर में पर्वतीय उत्थान मंच और वन विभाग की कॉलोनी के मध्य स्थित सड़क भी इसी प्रकार अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स भी मात्र कागजों तक सिमट कर रह गई है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं और महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य हैं। 'दि संडे पोस्ट' की छानबीन बताती है कि शहर के व्यापारी अतिक्रमण हटाने का भारी विरोध करते हैं। व्यापारी वर्ग का राजनीतिक रसूख प्रशासन पर हमेशा से ही भारी पड़ता आया है जिसका नतीजा है कि कुमाऊं का प्रदेश द्वार बदहाल हो चला है

संजय स्वार

उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद पहाड़ों से मैदानों की ओर पलायन में तेजी आई है। पहाड़ों और ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर हर कोई शहरों की ओर जाना चाहता है। जिस तेजी से शहरीकरण को बढ़ावा देती नजर आ रही है उस गति से शहरी नियोजनतंत्र को विकसित नहीं कर पा रही है। शहरीकरण का यही अव्यवस्थित ढांचा एक नई समस्या 'अतिक्रमण' को जन्म दे रहा है। राज्य के महत्वपूर्ण शहरों में शामिल हल्द्वानी उत्तराखण्ड के उन शहरों में शुमार है जो अतिक्रमण का शिकार हैं। यहां का प्रशासन महज खानापूर्ति के लिए अतिक्रमण हटाओ के अभियान छेड़ जनता की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं कर रहा है। अभी तक जितने अतिक्रमण हटाओ अभियानों की घोषणा की गई और उन पर ईमानदारी और सख्ती से अमल करने की इच्छा हुक्मुरानों और अफसरानों ने रखी होती तो हल्द्वानी शहर की तस्वीर काफी हद तक बदली होती। हल्द्वानी के नगर निगम बनने के बाद तो स्थिति बद से बदतर हो चली है। नगर निगम बनने के बाद राजनीतिक दलों को मेयर का पद मिल गया अधिशासी अधिकारी की कुर्सी नगर आयुक्त के रूप में अधिकारियों के हिस्से आ गई लेकिन हल्द्वानी शहर के लिए बाशिंदों की समस्याएं जस की तस हैं। हल्द्वानी शहर में विकास के तमाम दावों के बीच सिकुड़ती सड़कें, सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक जाम की समस्या बताती है कि समस्याओं के निदान के दावे महज जुबानी खर्च से ज्यादा कुछ नहीं है। नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग और पुलिस के संयुक्त अभियान महज फड़-खोखों वालों पर कार्रवाई तक समिति हैं। सिकुड़ती सड़कें और अतिक्रमित किए फुटपाथ सरकारी विभागों की काहिली की कहानी कहते हैं। शहर की नैनीताल रोड, बरेली रोड, रामपुर रोड से लेकर कालाढूंगी रोड भारी अतिक्रमण की शिकार हैं लेकिन नगर निगम और जिम्मेदार सरकारी विभाग इस समस्या से मुंह मोड़े हैं। अचानक नींद से जागते इन्हें अतिक्रमण हटाने की याद आती है लेकिन कुछ समय बाद ये फिर गहरी नींद में चले जाते हैं। हल्द्वानी के लोग १९९२ के समय को याद करते हुए कहते हैं कि तत्कालीन जिलाधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने तमाम राजनीतिक दबावों को दरकिनार करते हुए अतिक्रमण के खिलाफ जिस प्रकार सख्ती दिखाई थी उसका ही परिणाम था कि आज कालाढूंगी रोड और नैनीताल रोड इतनी चौड़ी दिखाई देती हैं। हालांकि राजनेताओं के दबाव के चलते उनको ज्यादा समय यहां टिकने नहीं दिया गया। उन्हें कुछ वक्त और मिला होता तो शायद आज हल्द्वानी का स्वरूप कुछ और निखरा होता। हल्द्वानी शहर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में लगने वाला ट्रैफिक जाम अतिक्रमण के कारण ही है। सबसे बुरा हाल हल्द्वानी के मुख्य बाजारों का है। दिन के समय अतिक्रमण से ग्रस्त मुख्य बाजारों की सूरत किसी गली सी हो जाती है। व्यापारियों ने अतिक्रमण को भी एक धंधा बना दिया है। बताया जाता है कि अधिकतर दुकान के आगे लगने वाले फड़ और ठेलों से दुकानदार अच्छी खासी रकम वसूलते हैं। व्यापारी नेता अतिक्रमण हटाने की बात जरूर करते हैं लेकिन अतिक्रमण हटाते समय व्यापारी एकता के नाम पर अतिक्रमण हटाने का विरोध करते ऐसे नेता सबसे आगे दिखाई देते हैं। गत् वर्ष दीपावली के वक्त अतिक्रमण हटाने गई सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह को व्यापारी विरोध के चलते अपनी कार्यवाही रोकनी पड़ी थी। अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तराखण्ड होईकोर्ट की पहल पर सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग ने कई स्थल चिह्नित कर कार्रवाई शुरू की गई थी लेकिन विरोध और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते प्रशासन को कदम पीछे खींचने पड़े।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया था जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक सदस्य सचिव तथा वन प्रभागीय अधिकारी समेत सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य बनाए गए थे। शुरुआत में यह टास्क फोर्स जोर-शोर से अतिक्रमण चिह्नित करती दिखी लेकिन अतिक्रमण हटाते समय प्रशासन हांफता नजर आया और सारी कवायदें ठंडे बस्ते में चली गईं। शहर में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए और चिह्नित करने के लिए ड्रोन से मैपिंग कर अतिक्रमण को चिह्नित करने की बात पुलिस अधिकारी ने तब कही थी। वक्त बीतने के बाद अब ड्रोन मैपिंग योजना की बात भी कही नहीं होती। रसूखदार रसूख के बल पर अतिक्रमण करने से परहेज नहीं करते। नैनीताल रोड पर वॉक वे मॉल और शहर की पॉश कॉलोनी कालिंदी कुंज में उस नाले को अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया जिससे शहर का पानी गौला नदी पर निकलता था। इस अतिक्रमण की भयावहता बरसात में दिखाई देती है जब पूरी नैनीताल रोड-नाले में तब्दील हो जाती है। इसी प्रकार हीरानगर में पर्वतीय उत्थान मंच और वन विभाग की कॉलोनी के मध्य से सुशीला तिवारी अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है लेकिन रसूखदारों के चलते इस पर प्रशासन की नजर नहीं जाती। इस बार २६ दिसंबर से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की घोषणा जोर-शोर से की गई थी लेकिन पहले ही दिन ये अभियान दम तोड़ गया। खास बात ये है कि सिंधी चौराहे के पास नगर निगम ही अतिक्रमणकारी निकला। नगर निगम की स्वयं की दुकानें अतिक्रमण के दायरे में आ रही हैं। आधी-अधूरी कवायदों और इच्छा शक्ति के अभाव के चलते भविष्य में अतिक्रमण हटाने की कवायद परवान चढ़ पाएगी इसमें संदेह है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दलों के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान किसी खतरे से कम नहीं होगा।

बात अपनी-अपनी

अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न उचित नहीं है। नगर निगम और प्रशासन व्यापारियों को विश्वास में लेकर समन्वय स्थापित करे। अतिक्रमण हटाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारियों का नुकसान भी न हो और अतिक्रमण भी हटे।

सुमित हृदयेश, विधायक, हल्द्वानी

अतिक्रमण के विषय में प्रशासन को हमेशा सजग रहना चाहिए। बाजार के अंतर्गत अत्यधिक ठेले इत्यादि लगते हैं, उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। बाहरी लोगों का सत्यापन जरूरी है। नाली और गूलों पर अतिक्रमण तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अतिक्रमित क्षेत्र सामुदायिक उपयोग का होता है। इस सार्वजनिक सम्पत्ति को बिल्कुल सजगता से प्रशासन व निगम का दायित्व है इनकी रक्षा करना।

डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला, निवर्तमान मेयर, नगर निगम हल्द्वानी

जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति अतिक्रमण हटाने के कार्य में जुटी है। अतिक्रमणों को चिह्नित कर हटाने की कार्रवाई गतिमान है। पक्के अतिक्रमण को तोड़ने के लिए संबंधित लोगों को नोटिस दिए गए हैं। निश्चित अवधि में वो अतिक्रमण नहीं हटाते तो प्रशासन उन्हें हटाएगा। कच्चे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है।

ऋचा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी

हम अतिक्रमण हटाने के कतई विरोध में नहीं हैं लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर उत्पीड़न करना गलत है।

हुकुम सिंह कुंवर, प्रदेश अध्यक्ष, देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखण्ड

'कन्यादान से पहले करें विद्यादान'

कन्यापूजन करते सीएम धामी

रोड शो के दौरान सीएम धामी और सांसद अजय टम्टा

दिकदर्शन रावत

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमालय से लगे जनपद बागेश्वर के कपकोट तहसील के केदारेश्वर मैदान में आयोजित चेलि ब्वारयूं कौतिक (मातृशक्ति उत्सव) कार्यक्रम में जनता को कई सौगात दे गए साथ ही वे बाबा बागनाथ की धरती पर कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर गए। जिसमें रुपए ९९७६४८ लाख की कुल ३७ योजना शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने १८८७०७ लाख की ११ योजनाओं का लोकार्पण एवं ८०८९४१ लाख की २६ योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरित भी किए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया और हस्तशिल्प और हस्तकला उत्पादों की भी सराहना की। सीएम ने तांबे के बर्तन में कला-कृतियां एवं रिंगाल की टोकरी भी बनाई। शहीदों की वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा चेलि ब्यारयूं कौतिक कार्यक्रम में अपार संख्या में उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं।

बागेश्वर जिले हेतु ९९ करोड़ ७७ लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास, बागेश्वर जनपद के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी एवं आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिलेगा। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में मातृ शक्ति के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मातृ शक्ति अपने परिवार के साथ ही समाज और प्रदेश हितों का भी ख्याल रखती हैं। मातृ शक्ति के सहयोग से ही समाज और राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव है। परिश्रम और मातृ शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्र की मातृ शक्ति शिक्षित होने से उस राष्ट्र का वर्तमान एवं भविष्य सुरक्षित रहता है। वहीं बेटियां भारतीय संस्कृति में 'कन्यादान' करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, परंतु हम सभी 'कन्यादान' से पहले 'विद्यादान' भी करें। आज देशभर में स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, उत्तराखण्ड में भी महिला स्वयं सहायता समूहों की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जो नए भारत की शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव-गांव में महिलाओं को घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से निरंतर काम कर रही है।

राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को ३० प्रतिशत आरक्षण देने के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना, नंदा गौरा मातृवंदना योजना और महिला पोषण अभियान जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करने के साथ ही धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया, प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर सरकारी भूमि में हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी निरंतर कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड में समान नागरिक आचार संहिता को भी लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने 'विकल्प रहित संकल्प' को पूर्ण करने हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि और उद्यान के नाम पर धड़ल्ले से जमीन खरीदने पर राज्य सरकार ने अंतरिम रोक लगाई है। यह रोक भू माफियाओं एवं गलत नीयत से जमीन खरीदने वालों पर लगी है। यदि कोई व्यवसाय उद्योग एवं किसी अन्य स्टार्टअप के लिए जमीन खरीदेगा, जिससे यहां के स्थानीय लोगों को फायदा मिले, तो उसका उत्तराखण्ड में स्वागत है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सांसद अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व उत्तराखण्ड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के तहत दुनिया भर से उद्योग जगत के लोगों को उत्तराखण्ड में बुलाया गया। आज उत्तराखण्ड के प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि पहली बार कपकोट क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री कपकोट क्षेत्र की प्रत्येक मांग को पूर्ण प्राथमिकता से लेते हैं। चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ ही जो भी मांग रखी गई वह पूरी हुई है।

जब पत्रकार हुए नाराज

प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत जिले के सभी जनप्रतिनिधि जहां मौजूद थे वहीं मीडिया कर्मियों के लिए कार्यक्रम में बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी न ही कवरेज करने की सुविधा दी गई थी यही नहीं सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार भी संतोष जनक नही था। जिससे जिला पत्रकार संघ और पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के सामने ही जमीन पर बैठकर विरोध जताया। जब पत्रकार कार्यक्रम स्थल से जाने लगे तब दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश परिहार ने उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन तब तक सभी पत्रकार स्थल छोड़ने का निर्णय ले चुके थे।

काव्योत्सव से मित्रता का पैगाम

काव्योत्सव में भारत-नेपाल के अतिथिगण एवं आयोजक

पुरस्कृत करते पश्चिमी नेपाल के पूर्व सीएम राजेन्द्र सिंह रावल

दिनेश पंत

सोरघाटी पिथौरागढ़ में पहली बार अंतराष्ट्रीय काव्योत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें भारत व नेपाल के ५० से अधिक साहित्यकारों व कवियों ने भाग लिया। ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय समिति पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित दो दिवसीय यह कार्यक्रम स्थानीय हीरादेवी भट्ट बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में दोनों देशों के साहित्यकारों ने अपनी साहित्यक रचनाओं का भी आदान-प्रदान किया। इस दौरान नेपाल से आए साहित्यकारों की पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। लेखक कृष्ण सिंह पेला के मुक्तक संग्रह 'फूलको प्रहार', कैलाश पाण्डेय की कविता संग्रह

'एकलव्य के देशमा', गणेश नेपाली के गजल संग्रह 'एकलव्य' का विमोचन हुआ। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में दोनों देशों के भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व ऐतिहासिक विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। कवियों ने दोनों देशों के संदर्भों पर काव्यपाठ भी किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र सिंह रावल रहे।

बतौर मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह रावल ने दोनों देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला और यह भी बताया कि क्या ऐसा किया जाए जिससे दोनों देशों के सबंधों में और मजबूती आए। इस दौरान उन समानताओं को भी रेखांकित किया गया जो दोनों देशों में एक से हैं। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों, कवियों, पत्रकारों ने इस बात पर भी चिंता प्रकट की कि आज दोनों देशों के पहाड़ मानव सुरक्षा, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, पलायन व मूलभूत बुनियादी सेवाओं के अभाव से गुजर रहे हैं। पहाड़ों का पानी व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही यहां के मानव संसाधन का उपयोग यहां के विकास के काम नहीं आ रहा है, जिस पर दोनों देशों को अमल करने की जरूरत है। पहाड़ की जनता लगातार अपनी जगह से विस्थापित हो रही है जिससे सांस्कृतिक सभ्यता पर भी खतरा पैदा हो रहा है। संवाद के जरिए यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि दोनों देशों को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

कार्यक्रम में उपस्थित भाषा प्रेमियों ने परिचर्चा के दौरान कहा कि एक साहित्यक पाठक होने के नाते हमारी जिज्ञासा होती है कि हम यह जानें कि दोनों देशों में साहित्यक क्षेत्र में क्या कुछ घटित हो रहा है? किस तरह की रचनाएं रची जा रही हैं? साहित्य कितना मुखर व प्रगतिशील है? वह शासन व जनता के स्तर पर कितना हस्तक्षेप कर पाने की स्थिति में है? वह आम आदमी के संघर्षों, पीड़ाओं का कैसे सहभागी बन रहा है? कार्यक्रम के मुख्य संयोजक साहित्यकार ड़ा पीताम्बर अवस्थी ने इस काव्योत्सव के आयोजन के संदर्भ में अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी सांझी साहित्यक संपदा रही है। दोनों तरफ विपुल मात्रा में साहित्य का सृजन हो रहा है। दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के देश में साहित्य सृजन की जानकारी होना जरूरी है। भारत के हिंदी भक्ति साहित्य एवं नेपाली भक्ति साहित्य में कई समानताएं दिखती हैं। भारतीय साहित्य की तरह ही नेपाली साहित्य में वादों और साहित्यक आंदोलनों का प्रभाव रहा है। हिंदी कविता की तरह नेपाली कविता में भी छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की तमाम विशेषताओं को देखा जा सकता है।

काव्योत्सव में सांझे साहित्य पर चर्चा के दौरान यह बात निकलकर आई कि जियारानी-मौलारानी का भड़ा, मालूशाही-राजुला, गंगनाथ-भाना बामनी, भियां कठायत-छियां कठायत, चैतालो-भेटौलो, सहदेऊ बालो-गोरीधाना का भड़ा, कालू भंडारी-उदयमाला जैसी गाथाएं दोनों देशों में समान रूप से प्रचलित हैं। फाग, सगुन, धमारी, चांचरी, जागर, न्यौली, भड़ा, भगनौला, होली, बग्वाल जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं में दोनों देशों में एकरूपता दिखती है। कुमाऊं में आठूं नेपाल के सुदूर पश्चिम में गौराष्टमी के रूप में मनाई जाती है। जौलजीवी के मेले, कैलाश मानसरोवर यात्रा, खतडुवा पर्व, बगवाल दोनों देशों में मनाया जाता है। हुडकेली, जागर प्रथा, जात मनाने की प्रथा भी दोनों देशों में प्रचलित है। इसी तरह भाषिक समानता पर चर्चा में यह बात सामने आई कि डोटेली, नेपाली, कुमाऊंनी, गढ़वाली, जौनसारी जैसी मध्य पहाड़ी भाषाओं में दोनों देशों में एकरूपता दृष्टिगोचर होती है।

सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से देखें तो गौरी की उपासना, महिलाओं का दीक्षांत समारोह, दूबधागो बांधने, भाद्र शुक्ल अष्टमी मनाने की प्रथा हो या फिर ऐपण, महालक्ष्मी चौकी या जन्मकुंडली लिखने की कला दोनों देशों में प्रचलित है। डिकरा बनाना हो या फिर वास्तुकला में भी दोनों देशों में एकरूपता दिखती है। नागरशैली में बने मंदिर, कत्यूरी शिखर शैली के मंदिर दोनों देशों में एक से हैं। दोनों देशों के धार्मिक संबंधों की समानता पर चर्चा में निकलकर आया कि शिव शक्ति की उपासना एवं अराधना, मष्टा संस्कृति, केदार संस्कृति हो या फिर देवताओं देवालय हों सभी समान हैं। उत्तराखण्ड में केदारनाथ ध्वज केदार थल केदार स्थित हैं तो पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, शिगास, केदार, रौला केदार, ग्वालेक केदार, काफलीकेदार, बूढ़ाकेदार, श्री केदार नेपाल में स्थित हैं। नंदा देवी कुमाऊं में है तो बुढ़ी नंदा बाजरा, नेपाल में है। नैनादेवी नैनीताल में है तो शुर्मा देवी, बाजारा नेपाल में है। नेपाली साहित्य के पास अपनी एक शानदार सांस्कृतिक विरासत है। भानुभक्त आचार्य नेपाल के तुलसीदास माने जाते हैं। इसी तरह मोतीराम भट्ट को नेपाल का भारतेंदु कहा जाता है। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल नेपाली साहित्य के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। नेपाल से प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं जन आकांक्षाओं का प्रतीक बनती रही हैं। इसमें मुखर होकर राजनीतिक अत्याचारों के साथ सामाजिक सुधारों के लिए आवाज उठती रही है। काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, समीक्षा और निबंध यानी हर तरह की विधाओं में नेपाली साहित्य संपन्न है।

उभर कर आए मुख्य बिंदु :

नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र सिंह रावल ने सुझाव दिया कि दोनों देशों के बीच अर्थपूर्ण वार्ताओं की आवश्यकता है। हमें अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पारस्परिक पारंपरिक सबंधों एवं सुरक्षा संबधों को कायम करने की आवश्यकता है। दोनों देशों के पड़ोसी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में लोकवार्ता विभाग की स्थापना की जा सकती है। लोकसंस्कृति के संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं पर्यटन के साथ दोनों प्रदेशों के आर्थिक, सामाजिक विकास की आवधारणा के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ सीमा क्षेत्र के दोनों राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कला, साहित्य के संरक्षण, संबर्द्धन एवं विकास अध्ययन अनुसंधान हेतु व्यवस्था करने की जरूरत है। तत्काल इस पर अमल करने की भी जरूरत है। काव्योत्सव में यह विचार भी निकल कर सामने आया कि अगर नेपाली साहित्य का हिंदी व हिंदी का नेपाली साहित्य में अधिक से अधिक अनुवाद हो तो इससे दोनों देशों के साहित्य को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। डिजिटल प्लेटफार्म पर भी एक दूसरे के साहित्यक योगदानों पर हम चर्चा कर सकते हैं। एक ऐसा लोकेल यानी परिवेश बना सकते हैं जिससे दोनों देशों का साहित्य विनिमय हो सकता है। एक ऐसी साहित्यक संस्था के गठन की जरूरत है जो दोनों देशों की भाषाओं में अनुवाद के कार्य के लिए काम करे। यह काम सरकारें या उनका भाषा अनुभाग भी कर सकता है। इससे दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ता मजबूत होगी। इसके साथ ही दोनों भाषाओं के समाचार पत्रों में भी दोनों देशों के साहित्कारों की जीवनी व उनके कृतित्व पर निरन्तर लेख प्रकाशित होते रहें। महत्वपूर्ण रचनाओं पर निरन्तर लेख समीक्षा प्रकाशित होती रहें। भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय काव्योत्सव जैसे कार्यक्रम नियमित अंतराल में चलते रहें जिससे दोनों देशों के साहित्यिक व सांस्कृतिक सबंधों को तो नया आयाम मिलेगा ही वहीं साहित्य का आदान-प्रदान भी होगा।

बात अपनी-अपनी

भारत व नेपाल एक सभ्यता व संस्कृति के निकटस्थ पड़ोसी देश हैं। उनके बीच प्राचीन ऐतिहासिक, परम्परागत, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध हैं। आवागमन के लिए खुली सीमाएं हैं। जन-जन के बीच वैवाहिक व गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। यहां सांझी संस्कृति, इतिहास, साहित्य व भाषा है। भारत के पांच प्रान्त व नेपाल के ४ प्रदेशों की सीमाएं इससे आपस में जुड़ी हैं। १८५० किमी की खुली सीमा है। अब जरूरत है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के जनस्तर के संबधों की प्रगाढ़ता को आगे बढ़ाने की। इस प्रकार के कार्यक्रमों में निरंतरता देना जरूरी है। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, लोकवार्ता के उत्थान के लिए मिलकर सहयात्री बनने की जरूरत है।

राजेंद्र सिंह रावल, पूर्व मुख्यमंत्री, सुदूर पश्चिम प्रदेश, नेपाल

इस अंतराष्ट्रीय काव्योत्सव के आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साहित्यकारों का समागम करना था। इसमें सांझी विरासत, संस्कृति व लेखन को साझा किया गया। नेपाल की नेपाली, भोजपुरी, मैथिली भाषा के साथ ही हिंदी की लिपि भी एक ही है। इन सभी भाषाओं में एक ही भाव का साहित्य सृजित होता है। नेपाल में राम कथा काफी लोकप्रिय है। नेपाल के हिंदी एवं नेपाली भाषा में रचित भक्ति साहित्य भारत एवं नेपाल के बीच सांस्कृतिक सेतु की तरह हैं। इन दोनों देशों की भावधारा एक रही है। यह काव्योत्सव दोनों देशों के साहित्यक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।

डॉ. पीताम्बर अवस्थी, साहित्यकार

दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं। हमारा सम्बन्ध अनादि काल से है। धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा एवं ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों राष्ट्रों में कई समानताएं हैं। खुली सीमाएं हैं। रिश्ते हैं। नातेदारी है। साथ ही सांस्कृतिक व साहित्यक संबध भी। दोनों देशों के बीच बेटी-रोजी का संबंध है। दोनों देशों के लोगों को अपने साझे इतिहास व परंपराओं पर गर्व रहा है। दोनों देशों में स्थानीय स्तर पर समृद्ध साहित्य रचा गया है। निश्चित तौर पर यह अंतराष्ट्रीय काव्योत्सव अपने उद्देश्यों में खरा उतरा है।

इं. ललित शौर्य, बाल साहित्यकार

जै जिया - जै उतरैणी

हरीश रावत
पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तरायण, हां मैं उत्तरायण की बात कर रहा हूं। उत्तरायण विशुद्ध साहित्यिक शब्द है और उत्तरायणी, हमारा उत्तराखण्डी अपभ्रंश है। मेरी उम्र के आस-पास के लोगों से २०-२५ साल पहले या बाद की सैकड़ों मधुर स्मृतियों में एक मधुर स्मृति उत्तरायण के त्यौहार की भी होगी। इस उत्तरायण को अलग-अलग ढंग से चित्रित किया जाता है। कुमाऊं के कुछ अंचलों में इसको घुघुतिया त्यौहार भी कहते हैं, मीठे-मीठे घुघुते व खजूरे बनते हैं और बड़े चाव से उनको खाते हैं। इधर मैंने घुघते और नारंगी की माला पहनाने का प्रचलन भी प्रारंभ किया था ताकि पुरानी यादें कुछ नएपन के साथ जीवांत रह सकें। मैंने बचपन में कैसे अपनी पहली उत्तरायण मनाई इसका मुझे स्मरण नहीं है। मगर मैं अनुमान से कह सकता हूं कि मेरे बड़े भाई रूद्र सिंह जी ने हाथ पकड़ कर व कंधे में बैठा कर बाखली में ले गए होंगे और पैलाग-पैलाग (प्रणाम) करना सिखाया होगा। क्योंकि मैंने भी अपने से लगभग दो साल छोटे भाई चंदन को उंगली पकड़कर बाखली के दूसरे घरों में पैलाग-पैलाग (प्रणाम) करने ले गया तो मैं कह सकता हूं कि मैंने भी अपनी पहली उतैरणी इसी तरीके से मनाई होगी। जब मैंने चंदन की पहली उत्तरायणी करवाई तो मेरी मां ने मेरे और चंदन के कंधे में एक-एक झोली डाली और उसमें जरा-सा गुड़ व चावल डाले और मुझसे कहा कि अपने भाई को तुम लेकर के जाओगे। पहले तुम्हारा ददा रूद्र सिंह तुमको लेकर के गया था, बल्कि कभी रूद्र सिंह जी, जब मैं बड़ा हो गया था तब भी बराबर चिढ़ाने के लिए मुझसे कहते थे कि फूल संक्रांति के दिन गांव की बाखली में घुमाते हुए मेरे कंधे टूट जाते थे, क्योंकि उनको मुझे कंधे में बैठा कर ले जाना पड़ता था और बहुधा मेरी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी इसी तरीके से जैसे चंदन को मैं उंगली पकड़-पकड़ करके ४-५ धेलियों में पैलाग (प्रणाम) कहने के लिए लेकर के गया और उसके एवज में लोग हमको जरा गुड़-चावल देते थे और फिर उस गुड़-चावल का मां मीठा भात बनाकर हम सब बच्चों को खिलाती थी, हम और पूरे गांव के बच्चे इसी तरीके से उतैरणी मनाते थे। जरा से बड़े हुए तो हमको जागरण की भी आदत डाली गई, उत्तरायणी के पहले दिन रात को जागरण में भजन-कीर्तन करते थे उसके बाद सुबह ४ बजे अंधेरे में गांव के धारे में जाकर के नाह कर लौटते थे और उतनी ठंड में आप अंदाज लगा सकते हैं कि मोहनरी में दिसंबर में कितनी कड़कड़ाती ठंड रहती होगी! लेकिन जवानी के अच्छे-अच्छे दिनों तक भी हमने उस परंपरा को बनाए रखा।

कहा जाता है कि इसी उत्तराखण्ड की प्रथम वीरांगना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मां भगवती जिया जो कत्यूरी राजवंश की राजमाता थी, उन्होंने रोहिल्ला आक्रांताओं से लड़ाई लड़ते हुए हल्द्वानी में गौला के किनारे चित्रशिला घाट पर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, आज भी वहां एक बड़ा सा पत्थर है जिसमें मां जियारानी की घाघरे की छाप दिखाई देती है और वहां चित्रशिला की गुफा में रहकर के मां जिया रानी ने कत्यूरी वीरों का नेतृत्व करते हुए रोहिल्लों को अपनी धरती में प्रवेश करने से रोका था। कहा जाता है कि उत्तरायणी की जागरण मां जिया रानी के वीरत्व को समर्पित होती है। आज भी चित्रशिला घाट में उत्तरायणी के पहली रात को लोग रात-जगा करते हैं और जै जिया के साथ मां जिया रानी को याद करते हैं। हम जरा-सा बड़े हुए तो फिर उत्तरायणी का त्यौहार बनाने के लिए बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में जाने लग गये। बागेश्वर का उत्तरायणी का मेला, कुमाऊं अंचल का सबसे प्रसिद्ध मेला है। इस मेले के साथ कई ऐतिहासिकताएं भी जुड़ी हुई हैं और जो बागेश्वर की उत्तरायणी है, उस उत्तरायणी के साथ उत्तराखण्ड की राजनीति का भी उत्तरायण हुआ था। कुली- बेगार प्रथा के खिलाफ १९२१ में एक जन आंदोलन जो भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, यहीं सरयू की घाट पर बागेश्वर में घटित हुआ था। वर्षों कुमाऊं और गढ़वाल में कई चीजें सामूहिक रूप से आगे बढ़ी। पहाड़ों के इस अंचल में कांग्रेस के अभ्योदय का इतिहास भी दोनों भूखंडों में करीब-करीब साझा है। कत्यूरी राजवंश की राजधानी जोशीमठ थी और जब कत्यूरी राजवंश का उद्भव हुआ था, वह भी करीब-करीब साझा इतिहास है। उसी तरीके से साझा इतिहास कुली-बेगार आंदोलन का भी है।

गढ़ केसरी अनसूया प्रसाद बहुगुणा जी के नेतृत्व में ककोड़ाखाल (सारी) में १२ जनवरी, २०२१ के दिन बेगार प्रथा का प्रतिकार हुआ था। दसज्यूला क्षेत्र के ८६ गांवों के लोगों ने श्री बहुगुणा के नेतृत्व में मालगुजार, आलम सिंह, थोकदार हयात सिंह, ऐतवारू लोहार, काला दास के साथ मिलकर कुली बेगार बर्दायश के रजिस्टरों को जला डाला था और अंग्रेज कमिश्नर को यहां से भागना पड़ा था। कुमाऊं संभाग में बद्री दत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी, भूपाल सिंह खाती जी, जमीदार वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहन सिंह मेहता जी, श्यामलाल शाह जी, चंद्र सिंह शाही जी, लक्ष्मण सिंह नेगी जी और सभी नामचीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस दिन सरयू बगड़ के किनारे पर इकट्ठा हुए और गांव-गांव के प्रधानों, थोकदारों, मालगुजारों ने अपने साथ लाए हुए कुली बेगार रजिस्टरों को आग के हवाले कर दिया। जब उनको जला करके सरयू में डालने की बात आई तो अंग्रेजों ने चुनौती दी। बद्री दत्त पांडे जी ने कहा कि यह बगड़ आज लाल बगड़ के नाम से जाना जाएगा। आप जितना खून बहाना है बहा दो लेकिन हमको आज रजिस्टर जलाने से कोई नहीं रोक सकता है, हम रजिस्टरों को जलाएंगे और अंनततोगत्वा घबराए हुए अंग्रेजों ने जनसैलाब को देखकर अपने कदम पीछे हटा दिये और रजिस्टर जलाए गए तथा सरयू में बहा दिए गए। उस ऐतिहासिक घटना को निरंतरता देने के लिए हर साल सरयू के बगड़ पर एक अभूतपूर्व दृश्य जो शायद ही देश के इतिहास में एक-दो स्थानों के अलावा कहीं और इस रूप में हर वर्ष मनाया जाता हो, पहले बहुत अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाया जाता था, दूर-दूर से लोग नगाड़े, रणसिंगे, बाजे लेकर के आते थे और राजनीतिक जागरण के साथ बागेश्वर उस समय एक व्यापारिक मंडी के रूप में परिवर्तित हो जाता था, कुमाऊं भर के व्यापारी, रोहिलखंड और दूर-दूर के व्यापारी भी बागेश्वर आते थे, तिब्बत और नेपाल के व्यापारी भी आते थे और वहां एक-एक महीने तक अपने हस्तशिल्प के बाजार को देश और दुनिया के सामने रखते थे, लोग दूर-दूर से हस्तशिल्प की चीजों को खरीदने के लिए बागेश्वर मेले में आते थे और आज भी आते हैं। मगर आज कुछ आधुनिकता भी आ गई है। यदि चौदास, व्यास, जौहार तथा जोशीमठ के कालीन/चुटकों के साथ अब भदोही के कालीन और चुटके भी बागेश्वर मेले में आने लग गए हैं और चीन निर्मित फर्नीचर भी दिखाई देने लग गया है। लेकिन पहले विशुद्ध रूप से स्थानीय हस्तशिल्प का भी एक विशाल मेला वहां लगता था, कुछ उत्पादों का मेला लगता था, आज भी उत्पादों का मेला लगता है, कृषि उत्पाद, बागवानी उत्पाद आज भी मन मोह लेते हैं। इन उत्पादों को देखकर के लगता है कि अब भी हमारी खेती, हमारी बागवानी, हमारी सब्जियां आज भी हमारे गांवों में जिंदा हैं। बड़े-बड़े कद्दू, ३-३, ४-४ हाथ लंबी लौकियां, बड़ी-बड़ी मूलियां, बड़े-बड़े माल्टे, खिले हुए नांरगी, बड़े-बड़े नींबू, गलगल, किन-किन उत्पादों का नाम लूं, ये सारे उत्पाद बागेश्वर में उत्तरायणी के मेले को आज भी अद्भुत छटा प्रदान करते हैं। लेकिन जिसको हमने, हमारी आंखों ने देखा था वह तो अद्भुत से भी अद्भुत था, व्यापारी मेला भी, कृषि उत्पादन का मेला भी, आधुनिक विचारों का मेला भी, सांस्कृतिक मेला भी। मैं जब सांसद चुना गया तो पहचाने जाने के डर से रात को किसी अलाव के पास में कंबल ओढ़ कर बैठ जाता था और रात भर उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक समृद्धि का आनंद लेता था, भग नौले, जोड़, पाठे सुनता था। कभी-कभी महिला और पुरुषों की टोलियां तो कभी-कभी एक महिला, एक पुरुष अलग-अलग जगह से पांठे और जोड़ शुरू करते थे तो उनकी सर्जनात्मक शक्ति, उनकी बौद्धिक शक्ति और उनके भावों का एक अद्भुत समागम दिखाई देता था। आज मेरा मन कहता है कि काश मैंने उस सबको संग्रहित किया होता तो उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति पक्ष का एक अद्भुत खजाना मेरे पास होता। कभी-कभी तो रात बीत जाती थी लेकिन प्रतिद्वंदी टीमें हार मानने को तैयार नहीं होती थी। पहले दूर-दूर के गांवों के लोग आते थे, मन में अपनी व्यथाओं को लेकर के थोड़े से आत्मिक सुख के लिए वह मेले में आते थे और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त देने का काम करते थे।

इस मेले ने हम जैसे न जाने कितने लोगों को राजनीति का अ, आ, क, ख भी सिखाया। यदि रामनगर का बसंत पंचमी का मेला और बागेश्वर की उत्तरायणी का मेला नहीं होता तो हरीश रावत राजनीति के कई पाठों को नहीं सीख पाता। यहीं हमने अपने बड़ों से शहर प्रतिक्षणा का भी पाठ पढ़ा, कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं होता था जिसके पांव बागेश्वर पहुंचने के लिए थिरकते नहीं थे व बागेश्वर मेला क्षेत्र की प्रतिक्षणा न करता हो। हम लोग नगाड़े, निशान और अपनी पार्टी का ध्वज लेकर पूरे बाजार भर में घूमते थे और उसके बाद बगड़ में आकर के इकट्ठा होते थे। अकेले कांग्रेस ही नहीं सारे राजनीतिक दल, छोटे-बड़े सब इस परंपरा को निभाते थे। मुख्य आकर्षण कांग्रेस रहती थी, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता गण भी आते थे, मुख्यमंत्री के रूप में नारायण दत्त जी भी आए। मैं भी वहां गया और भी बहुत सारे लोग गए, पदों के साथ गए लेकिन जो महत्व एक कार्यकर्ता के तौर पर जाने का सुख आज भी मैं आत्मिक रूप से अनुभव करता हूं, उस क्षण को याद करके ऐसी अनुभूति होती है कि हम एक महान परंपरा के ध्वजवाहक थे जिस परंपरा ने कभी इसी सरयू बगड़ पर अंग्रेजों को ललकारा था और इसीलिए हम अपनी राजनीतिक विचारधारा को जोश-खरोश व पूरी शक्ति के साथ रखने का काम करते थे। मैं पहली बार जब बागेश्वर गया था तो उस समय जिला युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बन गया था। लेकिन तब से लेकर शायद ही कोई उत्तरायणी छूटी होगी जिस उत्तरायणी में मैं बागेश्वर न पहुंचा हूं। इधर कुछ समय से व्यवधान आने लग गया है और फिर उत्तरायणी आ रही है। फिर बागेश्वर की यादें कचोट रही हैं, लेकिन शारीरिक असमर्थता के कारण इस बार जाने की स्थिति में मैं नहीं हूं। मगर वह भावनाएं उतनी ही जोश के साथ, कांग्रेस के साथियों के साथ होंगी जो हमारी पार्टी के शहर प्रतिक्षणा करेंगे और सरयू के बगड़ पर अपनी वैचारिक शक्ति को लोगों के सामने रखेंगे, भाजपा, उक्रांद सहित सभी पार्टियों और जन आंदोलनों के लोग भी आते थे, आज भी आयेंगे और आजादी के दौरान की रश्मों का निर्वहन करेंगे। मुझे याद है श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी जो विपक्ष के पहले या दूसरे निर्वाचित विधायक रहे थे जनसंघ के, मगर हर वर्ष एक छोटा सा माइक लेकर के बागेश्वर के बाजार में घूमते रहते थे और तीन दिन वहीं प्रतिक्षणा करते थे और चौथे दिन वहां से कपकोट के सरो बगड़ पर चलते थे, वह मेले के एक स्थाई भाव थे। यूं बीजेपी के बड़े नेता सोबन सिंह जीना जी आदि दूसरे लोग भी आते थे लेकिन गोविंद सिंह जी एक अलग सी रंगीनियत राजनीतिक झुंडली देते थे और कांग्रेस को खूब घोट-घोट करके गाली देते थे, उस समय यदि कहीं तेल के दाम १० पैसे भी बढ़ गए तो उत्तरायणी में गोविंद सिंह जी कांग्रेस की बूरी गत करते थे। आज जब मैं कभी-कभी सोचता हूं तेल इतने आसमान पर पहुंच गया है तो गोविंद सिंह जी को स्वर्ग में कितनी तकलीफ नहीं हो रही होगी! उस समय वह कांग्रेस को कोसते थे कि हे कांग्रेस वालो तुम्हारा नाश हो जाए तुमने हमारे घुघुतिया त्यौहार को भी हमसे छीन लिया है, तुमने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, गुड के दाम बढ़ा दिए हैं, पीसू (आटा) के दाम बढ़ा दिए हैं, यह उनका कहना होता था।

इस उत्तरायणी के मेले के साथ हमारी प्रतिबद्धता इतनी जबरदस्त थी कि एक बार दो दिन लगातार भयंकर बारिश हुई, जिस दिन शहर प्रतिक्षणा करनी थी। उस दिन इतनी मूसलाधार बारिश हुई, ऐसा लगा कि आज आसमान टूट पड़ेगा! बाजार में सब लोग घरों के अंदर दुबके पड़े थे, कोई बाहर निकल ही नहीं रहा था और जो लोग गांवों में थे वह लोग आए ही नहीं थे। मैं उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और टीआरसी बागेश्वर में रुका हुआ था, वहां कांग्रेस के लोग जैसे-तैसे भीगते हुए आए और हमने तय किया कि हम जाएंगे और अपने बुजुर्गों के कर्तव्य को निभाएंगे, हम नारे लगाते हुए निकल पड़े। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी पत्नी श्रीमती रेणुका रावत भी मेरे साथ नारे लगाते हुए, भीगते हुए मूसलाधार बारिश में सरयू के बगड़ पर पहुंची और उसने पूरी रश्म निभाई। विडंबना देखिए ३ बजे, जब मेला समाप्ति की ओर आ गया तो धीरे-धीरे आसमान छंटने लगा और थोड़ी धूप भी खिल आई। मुझे गर्व है इस बात का कि हमने अपने बुजुर्गों की उस रश्म को मूसलाधार बारिश में भी निभाया और कहा कि है स्वतंत्रता संग्राम के महावीरों तुम्हारी जो वंशावली है, वह वंशावली अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है।

आज उत्तरायणी को हम एक महापर्व के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि उत्तरायणी के मौके पर जिन पवित्र कार्यों का शुभारंभ होता है वो जनकल्याणकारी सिद्ध होती हैं। श्री राहुल गांधी जी भी दिनांक-१४ जनवरी, २०२४ से पूर्वोत्तर के मणिपुर से महाराष्ट्र के मुंबई तक ६७ दिनों की लगभग ६२०० किमी की भारत न्याय यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, उद्देश्य महान है लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना का। आज देश में एकाधिकार वादी प्रवृत्ति चरम की ओर बढ़ रही है, सामाजिक, राजनीतिक जीवन से संतुलन गायब हैं। जनता के सवाल, अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी व महंगाई, निरंतर बढ़ता भ्रष्टाचार, गरीब की जेब खाली हो रही है, कुछ लोग अरबों-खरबों के स्वामी बन रहे हैं। विकास किसका दायित्व है इस पर आज चर्चा नहीं हो रही है!! हम अपने ही देश के भाई-बहनों से एक काल्पनिक युद्ध लड़ रहे हैं। भय व दोहन को सत्ता पाने का माध्यम बनाया जा रहा है। एक अजीब-सी बेचैनी सर्वत्र व्याप्त है। देखते हैं इस बार की उत्तरायणी सार्थक परिवर्तन लाने में सफल होती है या नहीं होती है! राहुल गांधी जी इम्फाल से भारत न्याय यात्रा प्रारंभ करेंगे। बागेश्वर के बगड़ में कांग्रेस जन १९२१ के कुली बेगार रजिस्टर जलाओ अभियान की याद में परिवर्तन की हुंकार भरेंगे, मैं भी सुबह नहा-धोकर जै जिया कहकर के इस महाभियान में अपना योगदान दूंगा।

'जै जिया - जै उतरैणी' ।।

(यह लेखक के अपने विचार हैं।)

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 13 जनवरी, 2024

अडानी को 'सुप्रीम' राहत

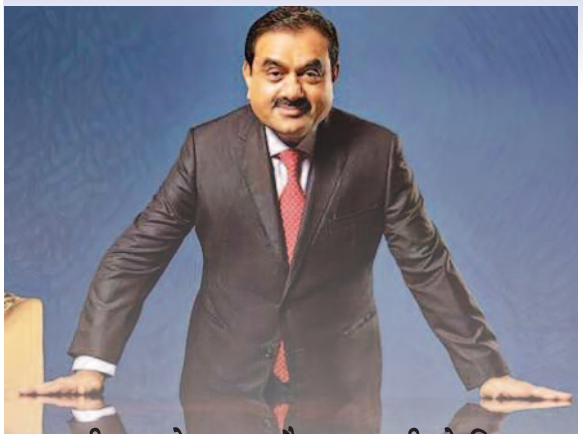

अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी के लिए यह साल चौतरफा सौगात लेकर आया। हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट बन गए। इस साल उनकी नेटवर्थ में 5.64 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तेजी आई है जबकि पिछले साल वह सबसे ज्यादा नेटवर्थ गंवाने वाले शख्स थे। नया साल आते ही उनकी किस्मत ने पलटी खाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में अपने फैसले में कहा है कि इस मामले की जांच सेबी ही करेगा और इसे एसआईटी या सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा

जीवन सिंह टनवाल

भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी दो साल पहले यानी २०२२ में दुनिया के तमाम अरबपतियों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप ३ अमीरों में शामिल रहे और साल २०२३ की शुरुआत में ही अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, जिसका अडानी के साम्राज्य पर इतना बुरा असर हुआ कि उनकी कुल संपत्ति का पांचवां हिस्सा महज दो दिन में ही साफ हो गया। इसके बाद यहां तक कहा जाने लगा था कि अडानी का साम्राज्य गहरे संकट की ओर है। लेकिन अब साल २०२४ के पहले ही हफ्ते में देश की सर्वोच्च अदालत से मिली राहत से अडानी ग्रुप पर छाए काले बादल छंटने लगे हैं।

अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सेबी को एफपीआई और एलओडीआर नियमनों पर उसके संशोधनों को रद्द करने का निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं है। सेबी ने २४ में से २२ मामलों में जांच पूरी कर ली है। अदालत ने कहा, 'सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में ३ महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।' कोर्ट का मानना है कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। इन्वेस्टर और कारोबारी जॉर्ज सोरोस और राकफेलर ब्रदर्स जैसे लोगों की फंडेड 'ओसीसीआरपी' २००६ में बनी एक इन्वेस्टिगेटिव संस्था है।

अडानी समूह को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह नियामकीय व्यवस्था के दायरे में नहीं आ सकता और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या ऐसी कोई भी चीज अलग से जांच के आदेश का आधार नहीं बन सकती। सेबी आगे बढ़ेगा और कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखेगा। यह साबित करने का कोई आधार नहीं है कि सेबी ने कदम उठाने में ढिलाई बरती। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि वर्तमान में मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है सरकार और सेबी शार्ट-सेलिंग पर हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए कानून के उल्लंघन के आरोपों, यदि कोई हो, की जांच करेंगे और इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और सेबी से नियामकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने को कहा है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने से इंकार किया है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी के लिए यह दिन चौतरफा सौगात लेकर आया। हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट बन गए। ग्रुप के शेयरों में करीब १२ फीसदी तक तेजी आई और ग्रुप का मार्केट कैप १५ लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। शेयरों में तेजी से अडानी की नेटवर्थ में भी ४०१ अरब डॉलर यानी करीब ३,३४,०६,७०,८५,००० करोड़ रुपए की उछाल आई और यह ८९९ अरब डॉलर पहुंच गई। इसके साथ ही वह अमीरों की लिस्ट में एक स्थान चढ़कर १४वें स्थान पर पहुंच गए। इस साल उनकी नेटवर्थ में ५६४ अरब डॉलर की रेकॉर्ड तेजी आई है जबकि पिछले साल वह सबसे ज्यादा नेटवर्थ गंवाने वाले शख्स थे। लेकिन नया साल आते ही उनकी किस्मत ने पलटा खाया है। सबसे ज्यादा अडानी एनर्जी साल्यूशन १५ फीसदी तक बढ़ गए। इसके बाद अडानी टोटल गैस १०, अडानी ग्रीन एनर्जी ८, अडानी पावर ५, अडानी इंटरप्राइजेज करीब ८ फीसदी और अन्य शेयर भी उछाल देखा गया।

अर्थशास्त्रियों और कानून विदों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह लगभग साफ हो चुका है कि सेबी की जांच सही रास्ते पर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सबूत के तौर पर मानने से इनकार किया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर लगे २४ आरोपों में से २२ को जांच में क्लीन चिट मिली है। हालांकि सेबी अभी २ और मामलों की जांच तीन महीने में पूरी करेगी। कोर्ट के अभी तक के फैसले से कहा जा सकता है कि अडानी ग्रुप पर कोई संकट नहीं है। ऐसे में अडानी ग्रुप पर निवेशकों का भरोसा पूरी तरह से लौट सकता है, जिस कारण अडानी ग्रुप के शेयर खरीदारों को फायदा होगा। इसके साथ ही कंपनी का कारोबार भी बढ़ेगा और अडानी ग्रुप का पूरी तरह से अपने व्यापार पर फोकस रहेगा।

इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी के आरोप

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अरबपति गौतम अडानी ने 'कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी' की है। पिछले महीने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता।

अडानी समूह के मुखिया ने दी प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सच्चाई की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा।'

कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला

पिछले साल २४ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हमें अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से सही मानने की जरूरत नहीं है। हिंडनबर्ग यहां मौजूद नहीं है, हमने सेबी से जांच करने को कहा है।

२४ जनवरी २०२३ को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ६ सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी जांच करने के लिए कहा था।

कोर्ट ने खारिज की याचिकाकर्ताओं की दलीलें

कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों की ओर से हितों के टकराव के संबंध में याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत सरकार और सेबी भारतीय निवेशकों के हितों को मजबूत करने के लिए कमेटी की सिफारिशों पर विचार करेंगे।

एक्सपर्ट कमेटी के पुनर्गठन की मांग की गई थी

एक याचिका में एक्सपर्ट कमेटी के पुनर्गठन की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि यह कमेटी के साथ बहुत अन्याय होगा और लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति में काम करना बंद कर देंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि मार्केट रेगुलेटर सेबी को सभी मामलों में जांच पूरी करनी होगी।

सेबी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग

सेबी की ओर से रिपोर्ट में देरी के कारण सुप्रीम कोर्ट में सेबी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग को लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा था कि सेबी को दी गई समय सीमा के बावजूद वह अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है और अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

सेबी जांच में अब तक क्या-क्या हुआ?

- 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाई थी और सेबी को भी जांच के लिए 2 महीने का समय दिया था।
- सेबी को 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सेबी ने सुनवाई के दौरान जांच के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी।
- बेंच ने इसे अगस्त तक बढ़ा दिया। यानी सेबी को अपनी जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कुल 5 महीने का समय मिला।
- 14 अगस्त को सेबी ने अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का समय और मांगा।
- 25 अगस्त को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। बताया कि 22 जांच फाइनल हो चुकी हैं और 2 अधूरी हैं।
- 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कहा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सही मानने की जरूरत नहीं।
- 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में अपने फैसले में कहा कि इस मामले की जांच सेबी ही करेगा और इसे एसआईटी या सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

कमेटी सार्वजनिक कर चुकी है रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच रिपोर्ट १९ मई २०२३ को सार्वजनिक कर चुकी है। कमेटी ने कहा था कि अडानी के शेयरों की कीमत में कथित हेरफेर के पीछे सेबी की नाकामी थी, अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। कमेटी ने ये भी कहा था कि ग्रुप की कंपनियों में विदेशी फंडिंग पर सेबी की जांच बेनतीजा रही है।

क्या थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट

२५ जनवरी २०२३ को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में ३२ हजार शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में ८८ प्रश्नों को शामिल किया। इसमें दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि तीन साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से गौतम अडानी की संपत्ति एक अरब डॉलर से बढ़कर १२० अरब डॉलर हो गई है। इस दौरान इस समूह की ७ कंपनियों के शेयर औसत ८१९ फीसदी बढ़े हैं।

कई देशों में हैं मुखौटा कंपनियां

रिपोर्ट में मॉरीशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक फैले टैक्स चोरी वाले देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों के एक वेब का विवरण है। इसका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। फंड की हेराफेरी भी की गई थी। शोध में अडानी समूह के पूर्व अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात करना, हजारों दस्तावेजों की समीक्षा करना और आधा दर्जन देशों में दौरा शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि बड़े पैमाने पर शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है। समूह की सात प्रमुख कंपनियों के मूल्य को देखें तो यह फंडामेंटल आधार पर मूल्यांकन से ८५ फीसदी नीचे हैं।

अडानी ग्रुप पर क्या हैं हिंडनबर्ग के आरोप

1. अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उसके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट कर बढ़ाया।
2. मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया। आठ साल के दौरान पांच सीएफओ बदले।
3. ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85 फीसदी तक ज्यादा यानी स्काय रॉकेट वैल्यूएशन।
4. अडानी ग्रुप पर 2 .20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जो उसकी कंपनियों की हैसियत से ज्यादा है।
5. मॉरीशस और दूसरे देशों की कंपनियों में पैसे भेजे। उन कंपनियों ने अडानी के शेयर खरीदे।

हिंडनवर्ग रिपोर्ट के बाद धड़ाम हुए थे शेयर

गौरतलब है कि २४ जनवरी २०२३ को अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयर तेजी से गिरने लगे थे। सेबी की जांच के बाद २४ नवंबर को अडानी ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी। इसमें सेबी पर लगाए जा रहे आरोपों को नकारते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद से ही इसके शेयरों में तेजी आनी शुरु हो गई थी वहीं अब तीन महीने बाद अडानी के दो अन्य मामलों में फैसला आएगा।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत संचालित कल्याणकारी योजनाएं

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

नंदा गौरा योजना

नंदा गौरा योजना का मुख्य उद्देश्य

(1.)कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना

(2.)बाल विवाह रोकना

(3.)समाज में लैंगिक असमानता एवं सामाजिक असमानता को दूर करना

(4.)संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना

(5.)कन्या उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना

लाभार्थी वर्ग एवं देय लाभ–

क्र0सं0	लाभार्थी वर्ग	धनराशि
1.	कन्या शिशु के जन्म पर-	₹11,000/-
2.	बालिका के कक्षा-12 उत्तीर्ण करने व स्नातक/ डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश एवं अविवाहित होने पर-	₹51,000/-

इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 जीवित बालिकाओं को ही दिया जाएगा।

योजना का उद्देश्य-

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं, ताकि माँ और बच्चे को स्वास्थ्य और पोषण प्राप्ति के साथ माँ को श्रम के नुकसान की प्रतिपूर्ति भी हो सके।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु पात्र लाभार्थी जो समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गो के निर्धारण के मानदंड निम्नलिखित हैं-

पात्रता एवं शर्तः- योजना के अन्तर्गत पात्र महिला अपने पहले 2 जीवित बच्चों के लिए योजना का लाभ नियमानुसार प्राप्त कर सकती हैं

क्र. सं.	लाभार्थी पात्रता निर्धारित मापदण्ड	आवश्यक दस्तावेज
1.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र
2.	जो महिलाएं आंशिक रूप से (40%) या पूरी तरह से विकलांग हैं (दिव्यांग जन्य)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र
3.	बी.पी.एल. राशन कार्ड की महिला धारक ।	राशन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति
4.	आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत महिला लाभार्थी।	कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति
5.	ई–श्रम कार्ड धारण करने वाली महिलाएं।	कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति
6.	महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं	कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति
7.	मनरेगा जॉब कार्ड धारण करने वाली महिलाएं (विगत वित्तीय वर्ष में रोजगार प्राप्ति के दिन)	कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति
8.	जिन महिलाओं की शुद्ध पारिवारिक आय रुपये 8 लाख प्रति वर्ष से कम हैं।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र
9.	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आँगनवाड़ी कार्यकर्ती/आँगनवाड़ी सहायिका/आशा	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

- पहले बच्चे के मामले में रुपए 5000 की धनराशि दो किस्तों में दी जाएगी।
- महिला का दूसरा बच्चा अगर लड़की हो तो उसे एक किश्त में रू.6000 का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी की आधार संख्या के आधार पर ही योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है ताकि किसी भी दोहराव (Duplication) या कदाचार (Malpractice) से बचा जा सकें।

नीचे दी गई तालिका में दी गई शर्तों के अनुसार दो किश्तों में नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा।

शर्तों एवं किश्तों का विवरण		
किश्त	शर्तें	धनराशि
प्रथम किश्त	आँगनबाड़ी केंद्र में एमएएल की तारीख से 6 महीने के भीतर गर्भावस्था के पंजीकरण एवं कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच पर करने पर-	रु 3,000/-
द्वितीय किश्त	1. बच्चों के जन्म पंजीकरण कराने पर 2. बच्चों ने बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी तथा हेपेटाइटिस बी तथा पहले चक्र का टीकाकरण पूर्ण करने पर-	रु 2,000/-

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना

योजना का उद्देश्यः- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का मुख्य उद्देश्य महिला एवं नवजात शिशु को समुचित पोषण प्रदान करना है। किट में पोषण, स्वच्छता एवं सफाई से सम्बंधित सामग्री लाभार्थी वर्ग को दी जाती है।

लाभार्थीः- इस योजना का लाभ एक परिवार की दो बालिकाओं के जन्म पर दिया जाता है, जो निर्धारित पात्रता पूर्ण करते हैं।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु विस्तृत पात्रता, शर्तों एवं जानकारी जनपद पौड़ी के अंतर्गत संचालित निकटतम बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय पौड़ी से प्राप्त की जा सकती है।

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 13 जनवरी, 2024

अबकी बार फिर हसीना सरकार?

जीवन सिंह टनवाल

भारत के दो पड़ोसी देशों-पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस वर्ष आम चुनाव होने जा रहे हैं। बांग्लादेश में सात जनवरी को मतदान होना है। वहां का विपक्ष इन चुनावों के बहिष्कार की घोषणा कर चुका है। उसका आरोप है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना नहीं है। पश्चिमी देश भी उनकी कार्यशैली से नाराज हैं लेकिन बीते पंद्रह बरसों से सत्ता में काबिज हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश एक सम्पन्न राष्ट्र बन उभरा है जिसके चलते आम जनता का एक बड़ा तबका एक बार फिर से शेख की ताजपोशी चाह रहा है। ऐसे में तमाम विरोधों के बावजूद उनका एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनना तय प्रतीत हो रहा है

साल २०२४ में दुनिया के कई मुल्कों में आम चुनाव होने हैं लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा एक ओर जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी को लेकर हो रही है वहीं दूसरी तरफ पकिस्तान और बांग्लादेश की चर्चा भी जोरों पर है। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान जेल से निकलकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंच पाएंगे या पाकिस्तान लौटे नवाज गद्दी संभालेंगे? बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बनेगी या खालिदा जिया की पार्टी हुकूमत को बदल देगी? ऐसे सवाल सिर्फ भारत में नहीं पूछे जा रहे, बल्कि पड़ोसी देशों की जनता की जुबान पर ये ही सवाल है कि अबकी बार किसकी सरकार?

इनमें सबसे पहले जिस देश में आम चुनाव होने वाला है वो बांग्लादेश है। यहां सात जनवरी को आम चुनाव के लिए मतदान होना है लेकिन इसके परिणाम से पहले ही सत्तारूढ़ आवामी लीग पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। क्योंकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) चुनाव का बहिष्कार कर रही है और वहीं उसके कई नेता जेल में हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ आवामी लीग लगातार चौथी बार संसदीय चुनाव जीतने जा रही है।

सबसे बड़े विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि उनका प्रधानमंत्री शेख हसीना में भरोसा नहीं है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएंगी। उनकी मांग है कि वो पद छोड़ दें और एक तटस्थ अंतरिम सरकार की निगरानी में चुनाव की अनुमति दें। इस मांग को हसीना खारिज कर चुकी हैं और इस कारण बैलेट पेपर पर सिर्फ आवामी लीग, उनके सहयोगी या स्वतंत्र उम्मीदवार ही नजर आएंगे। खास बात यह कि भारत के लिए यह चुनाव बहुत मायने रखता है इसलिए भारतीयों की दिलचस्पी लाजमी है।

बीएनपी ने क्यों किया चुनाव का बहिष्कार?

बांग्लादेश में विपक्ष को दरकिनार करते हुए चुनाव होने जा रहे हैं। विपक्ष ने हसीना सरकार पर अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगाया है। विपक्ष की मांग थी कि सत्तारूढ़ अवामी लीग प्रमुख हसीना आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें और एक तटस्थ अंतरिम सरकार की निगरानी में चुनाव कराए जाएं। प्रधानमंत्री हसीना ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया, जिससे बाद बीएनपी ने चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया।

बीएनपी ने क्या आरोप लगाए हैं?

बीएनपी के दिग्गज नेता अब्दुल मोईन खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र मर गया है। हम जनवरी में जो देखने जा रहे हैं, वो फर्जी चुनाव हैं। प्रधानमंत्री हसीना पिछले कुछ सालों में तेजी से निरंकुश हुई हैं। हसीना सरकार ने २० हजार से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी आरोपों में गिरफ्तार किया है, जबकि लाखों की संख्या में पार्टी के कार्यकार्ताओं पर केस दायर किए गए हैं।

चुनाव बहिष्कार पर सरकार का पक्ष?

विपक्ष के चुनाव बहिष्कार को लेकर सरकार के कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा, चुनाव लोगों की वोटिंग में भागीदारी से निर्धारित होते हैं। इस बार चुनाव में बीएनपी को छोड़कर बाकी कई राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। मैंने बीएनपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखने के आरोपों की जांच की और ये अधूरी जानकारी है। २००१ और २००४ के चुनावों के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के मामलों में पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं।

कितने सही हैं विपक्ष के आरोप?

हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में विपक्षी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए इसे हसीना सरकार की दमनकारी नीति बताया गया था। आंकड़े बताते हैं कि हसीना सरकार के कार्यकाल में राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारियां, हत्याएं और शोषण बढ़ा है। कई विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में जबरन जेलों में बंद किया गया है। आलोचकों का तर्क है कि चुनाव से पहले बीएनपी को कमजोर करने के लिए सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है।

भारत के साथ कैसे हैं बांग्लादेश के रिश्ते?

पश्चिमी देशों की आलोचना के बाद भी बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। यह उसकी बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ों का निर्यातक है। भारत भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश के साथ खड़ा नजर आता है और दोनों देशों के बीच २ हजार करोड़ डॉलर से ज्यादा का सालाना व्यापार होता है। हसीना सरकार में बांग्लादेश- भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं और भारत को चीन-पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की जरूरत है।

जानकारों का कहना है कि भारत बांग्लादेश के रास्ते अपने सात उत्तर-पूर्वी राज्यों में सड़क और नदी परिवहन चाहता है। साथ ही भारत 'चिकेंस नेक' को लेकर चिंतित है। ये एक २० किलोमीटर का कॉरिडोर है जो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच से निकलता है और उत्तर-पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। वर्ष २००९ में सत्ता में लौटने के बाद हसीन ने भारत का पक्ष लेते हुए उन जातीय उग्रवादी समूहों के खिलाफ काम किया जो भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सक्रिय थे और सीमा पार से ऑपरेट करते थे। साथ ही ये भी चिंताएं हैं कि अगर ढाका पर और दबाव डाला गया तो वो चीन की ओर भी जा सकता है। बीजिंग पहले से ही बांग्लादेश में अपनी पहुंच बनाने के लिए बेकरार है क्योंकि वो भारत से भी मुकाबला करना चाहता है।

गौरतलब है कि करीब ७५ साल की शेख हसीना साल २००९ से लगातार सत्ता में है। वह २०२४ में भी रिकॉर्ड पांचवीं बार पीएम पद की दावेदार हैं। आम चुनाव में वह जीतीं तो किसी देश की लगातार पांच बार चुनी हुई प्रधानमंत्री रहने वाली दुनिया में अकेली महिला नेता हो जाएंगी। बांग्लादेश की संसद को जातियों संसद या हाउस ऑफ द नेशन कहा जाता है। २०० एकड़ में फैली जातियों संसद की नई इमारत १५ फरवरी १९८२ को बनकर तैयार हुई थी। बांग्लादेश की संसद में कुल ३५० सीटें हैं। इनमें से ५० सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। संसद में ३०० सदस्य वोटिंग के जरिए चुने जाते हैं और महिलाओं के लिए रिजर्व ५० सीटें वोट शेयर के आधार पर बांटी जाती हैं। संसद में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करने के मामले में दुनिया में बांग्लादेश ही एकमात्र मुस्लिम-बहुल देश है।

शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की एक अलग तस्वीर सामने आई है। मुस्लिम बहुल राष्ट्र जो कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल था, उसने हसीना के कार्यकाल में ऐतिहासिक आर्थिक प्रगति हासिल की है। इस क्षेत्र में ये सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था से भी आगे निकल रही है।

इसकी प्रति व्यक्ति आय बीते दशक में तीन गुनी हो गई है और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि बीते २० सालों में ₹५ करोड़ से अधिक लोग गरीबी से निकले हैं। देश के अपने फंड्स, लोन्स और विकास मदद से हसीना की सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं जिसमें उनकी सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना ₹९ अरब डॉलर की पद्मा ब्रिज एक है। यह योजना गंगा के किनारे बन रही है। माना जा रहा है कि यह पुल उसकी जीडीपी में ₹१२३ फीसदी की बढ़ोतरी लाएगा।

न्यायिक प्रताड़ना रोकने की मांग

पिछले साल अगस्त में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन और यूटू लीड सिंगर बोनो समेत १७० से अधिक दुनिया की प्रमुख हस्तियों ने नोबेल विजेताओं मोहम्मद यूनुस की 'लगातार न्यायिक प्रताड़ना' रोकने की मांग की थी लेकिन इस बीच आम चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉ. मोहम्मद यूनुस को साल २०२४ के पहले ही दिन यानी एक जनवरी को एक अदालत ने श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में छह महीने जेल की सजा सुनाई है।

सात जनवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले हुए इस घटनाक्रम को यूनुस के समर्थकों ने राजनीति से प्रेरित बताया है। श्रम अदालत की न्यायाधीश शेख मेरिना सुल्ताना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उनके खिलाफ श्रम कानून का उल्लंघन करने का आरोप सिद्ध हो चुका है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि यूनुस को एक व्यावसायिक कंपनी के तीन अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण टेलीकॉम के अध्यक्ष के रूप में कानून का उल्लंघन करने के लिए छह महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

दूसरी तरफ विपक्ष की प्रमुख नेता खालिदा जिया इस समय भ्रष्टाचार के मामले में नजरबंद हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। वहीं जमीन पर बीएनपी के पास कोई करिश्माई नेता नहीं है। विपक्षी नेताओं और समर्थकों की लगातार गिरफ्तारी और सजा देने के बाद यह स्थिति और भी जटिल हो गई है। विपक्षी दलों का तर्क है कि चुनाव से पहले बीएनपी को कमजोर करने के लिए आवामी लीग ने जानबूझकर ऐसा किया है।

मानवाधिकार को लेकर चिंतित संयुक्त राष्ट्र

बांग्लादेश में लगातार बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां चिंतित हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय एशिया-पैसिफिक के प्रमुख रॉरी मुंगोवेन का कहना है कि बांग्लादेश में वर्तमान परिदृश्य एक ही घटना के मामले में हजारों विपक्षी पार्टी कार्यकर्ताओं को घेरने जैसा दिखता है।

इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के दूतों के एक समूह ने बीते नवंबर में भी चेताया था कि न्यायिक सिस्टम को हथियार की तरह इस्तेमाल करके पत्रकारों, मानवाधिकार और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कम हुई है और मूलभूत मानवाधिकार को नुकसान पहुंचा है। लेकिन बांग्लादेश के वर्तमान कानून मंत्री हक का कहना है कि सरकार का न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है। देश में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है।

मानवाधिकार समूहों को न केवल बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और सजाएं चिंता में डाल रही हैं बल्कि साल २००९ से अब तक सुरक्षाबलों की हिरासत में हत्याओं और जबरन गायब कर देने के सैकड़ों मामले उनके पास हैं। इस तरह के दुर्व्यवहार के पीछे खुद के हाथ होने को सरकार पूरी तरह खारिज करती है साथ ही वो इन मामलों की जांच करना चाह रहे हैं।

साल २०२१ में कुख्यात पैरा-मिलिट्री फोर्स रैपिड एक्शन बटालियन और उसके सात वर्तमान-भूतपूर्व अफसरों पर पाबंदी लगाने के अमेरिका के फैसले के बाद हिरासत में हत्याओं की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि अमेरिका के सीमित प्रतिबंधों के कारण बांग्लादेश में मानवाधिकार स्थिति ठीक नहीं हुई है। इसी वजह से कुछ राजनेता पश्चिमी देशों की ओर से और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

#GetYourSelfPlaced®

First Choice

For the Brightest of Minds

GALGOTIAS UNIVERSITY

offers edge to its students with **Top-Notch Placements, World Class Research Environment & Academic Excellence**

₹1.5 CRORE — OpenZeppelin
₹44 LACS — Microsoft
₹36 LACS — AUTODESK
₹33 LACS — COMMVAULT

Suryansh Pratap B.Tech, CSE Student
Guru Prakash Singh B.Tech, CSE Student
Tanishk Merothiya B.Tech, CSE Student
Sakshi Gaur B.Tech, CSE Student

We are committed to **carry forward the vision** of our Visionary Honourable Prime Minister **Shri Narendra Modi Ji** of **making India a Vishvaguru** and the dream of our Dynamic Honourable Chief Minister of Uttar Pradesh **Shri Yogi AdityaNath Ji** for making the **State of UP a truly Global Knowledge Superpower.**

ADMISSION OPEN 2023-24 for CAREER-FOCUSED UG / PG / Ph.D. DEGREES in

- Computing Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics & Communication Engineering
- Mechanical Engineering
- Civil Engineering
- Design
- Education
- Nursing
- Liberal Education
- Media and Communications Studies
- Law
- Agriculture
- Basic & Applied Science
- Finance & Commerce
- Pharmacy
- Medical & Allied Sciences
- Business
- Hospitality & Tourism
- Polytechnic

GALGOTIAS UNIVERSITY

(Under the Uttar Pradesh Private Universities Act No. 12 of 2019)

For the complete list of programmes offered and to apply online visit:
https://admissions.galgotiasuniversity.edu.in
www.galgotiasuniversity.edu.in

Plot No.2, Sector 17-A, Yamuna Expressway, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh, India.

Call @ 0120-4370000,
+91-97173 00418, +91-95828 47072
+91 99710 26125

Scan to know more

NAAC A+

Accreditation in First Cycle

This makes Galgotias University the **only private university in Uttar Pradesh** with the **highest NAAC score** and the **second highest amongst state private universities in the entire country** with a NAAC score of 3.37 out of 4 awarded by NAAC in the **First Cycle of NAAC Accreditation.**

Strategic Location

Galgotias University is located in the **midst of a Commercial/Industrial hub** & is located minutes away from upcoming **Noida International Airport.** The strategic location will help students gain access to opportunities as new investments to the tune of **35 Lakh Crore are planned, which shall create over 25 Lakh jobs in the Greater Noida region alone.**

Record Breaking Placements

Galgotias University has **broken all previous records** for placements with **800+ recruiters** giving Galgotias students multiple job offers: some of the recruiters are Infosys, Cognizant, Wipro and more.

Research Excellence & Awards

Galgotias University **Ranked Top 5 in India** as per the Indian Patent office Report for Academic Institutes and Universities, **filled 417 patents**

Galgotias University **Ranked in PLATINUM BAND (GRADE A++)** for **Institution of Academic Excellence** OBE Rankings 2022

Grade A++ PLATINUM BAND OBE RANKINGS 2022

Achieves excellence in quality education, & implementation of the latest teaching-learning methodologies, including the outcome-based education models.

The **Highest Benchmark** of **Academic Excellence, Placements & Research** for **Computer Science Engineering, Mechanical Engineering, Electronics & Communications, Engineering, B.Pharm** and **MBA**

NBA NATIONAL BOARD of ACCREDITATION ACCREDITED Tier 1

Students who graduate in the above mentioned NBA accredited programmes during the validity period of accreditation will be deemed to have graduated with an NBA accredited degree.

Galgotias University **Ranked #59 in India** (Pharmacy Category) by NIRF (National Institutional Ranking Framework) 2022

nirf NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK

#93 Management #147 Engineering

TOP RANKED BY INDIA TODAY

Galgotias University **Ranked#1** in India in Academic and Research Excellence as per India Today - **MDRA Best Universities Survey 2022.**

Galgotias University **School of Law Ranked #3** in India in Academic Excellence by **INDIA TODAY-MDRA Survey - July 2022**

Galgotias University has been listed in the Band **"Excellent" for "Innovation & Entrepreneurship Development".** Under University & Deemed to be University (Private / Self Financed) (Technical) in the AIIRA Ranking 2021.

ARIIA

Ranking#2 in Uttar Pradesh Ranking#46 in India

Thank You India! for **your continuous trust** in us, **Yet another milestone in our glorious success story.**

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency

Galgotias University is amongst **top 8 most preferred universities** in the country as per **CUET (Common University Entrance Test) applications.** Galgotias University **received record breaking 399,373 applications.**

School of Business Galgotias University **Ranked#2 in North India by TOP B-Schools Under Private Universities (Zonewise)**

OPEN

Galgotias University has been awarded **IAR-Placement Audit (5 stars) indicating HIGHEST performance capability in placing its students.**

Infomerics Analytics & Research

Galgotias University, School of Hospitality & Tourism, India is ranked among the **TOP 50 Best Hospitality and Hotel Management Schools** in the World for 2023 as per CEOWORLD, USA

CEOWORLD Magazine

Galgotias University awarded as the star performing institute in internships with an **All India 6th Rank in AICTE - EduSkills virtual internship programme 2022.**

EduSkills® Nation Building Through Skills

National Employability Award 2023 (AMCAT Test) for School of Computing Science and Engineering, Galgotias University on account of students performance being among the top 10% Nationally.

रेलमंत्री की हत्या के आरोप से घिरीं इंदिरा

अपूर्व
editor@thesundaypost.in

जनवरी, 1975 की शुरुआत इंदिरा गांधी के लिए नई समस्या लेकर आई। भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त उनके करीबी सहयोगी रेलमंत्री ललित नारायण मिश्रा की 2 जनवरी के दिन बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में एक बम विस्फोट के जरिए हत्या कर दी गई। मिश्रा इंदिरा सरकार के लिए भारी समस्या बन चुके थे इसलिए उनकी हत्या कराने का आरोप विपक्षी दलों ने सीधे प्रधानमंत्री पर लगाने में देरी नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन चलते ताकत पा रहीं 'विदेशी ताकतों' को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया था। प्रधानमंत्री का मानना था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी 'सीआईए' की मदद से 'आनंदमार्गियों' ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है

यह आंदोलन जेपी के नेतृत्व में पहले बिहार फिर देश के अन्य हिस्सों में तेजी पकड़ने लगा। कई स्थानों पर हिंसा की वारदातें भी शुरू होने लगी थीं। जेपी ने अपने समर्थकों से अहिंसा की अपील कर 'हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा' नारे का वस्तुतः पालन करने को कहा था। इस आंदोलन के दौरान रामगोपाल दीक्षित द्वारा रचा गया एक गीत आंदोलन का गीत बन तब देश भर में गूंजने लगा था-

जय प्रकाश का बिगुल बजा तो, जाग उठी तरुणाई है
तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है
आज चलेगा कौन देश से, भ्रष्टाचार मिटाने को
बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को।
आज देख लें कौन रचाता, मौत संग सगाई है
तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है
पर्वत की दीवार कभी क्या, रोक सकी तूफानों को
क्या बंदूकें रोक सकेंगी, बढ़ते हुए जवानों को
चूर-चूर हो गई शक्ति वह, जो हमसे टकराई है
तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है
लाख-लाख झोपड़ियों में तो, छाई हुई उदासी है
सत्ता-सम्पत्ति के बंगलों में, हंसती पूरणमासी है
यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं
तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है
सावधान पद या पैसे से, होना है गुमराह नहीं
सीने पर गोली खा कर भी, निकले मुख से आह नहीं
ऐसे वीर शहीदों ने ही, देश की लाज बचाई है
तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है
आओ कृषक, श्रमिक, नागरिकों, इंकलाब का नारा दो
कविजन, शिक्षक, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो
फिर देखें हम सत्ता कितनी, बर्बर है बौराई है
तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है
जयप्रकाश का बिगुल बजा तो, जाग उठी तरुणाई है।

जेपी आंदोलन की तीव्रता के आगे लेकिन इंदिरा गांधी झुकने को तैयार नहीं हुईं। उन्होंने शुरुआत में तो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब रक्षात्मक शैली में दिया लेकिन बाद में उन्होंने सीधे जेपी को अपने निशाने पर रखना शुरू कर डाला -'भ्रष्टाचार उतना व्यापक नहीं है जितना कहा जा रहा है, ललित बाबू (ललित नारायण मिश्रा, इंदिरा सरकार में रेलमंत्री) और बंसीलाल (हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री) ने कोई गलत काम नहीं किया है, मेरा पुत्र होनहार व परिश्रमी युवक है, वह कुछ कर दिखाना चाहता है पर दूसरों को इससे ईर्ष्या होती है, उसकी मारुति योजना में कोई गलत काम नहीं हुआ है... जेपी 'कन्फ्यूज्ड' आदमी हैं। वह खुद नहीं समझते कि वे क्या कह व कर रहे हैं, 'फ्रस्ट्रेटेड' हैं, कभी कोई पद नहीं मिला तो अब सत्ता हथियाने की सोच रहे हैं... उनका आंदोलन प्रतिक्रियावादी है, कुटिल शक्तियों से नियंत्रित है, आनंद मार्ग और जनसंघ की मदद से चलाया जा रहा है।'

जयप्रकाश के नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान ही एक अन्य प्रकरण चलते इंदिरा गांधी देश का ध्यान कुछ अर्से के लिए 'सम्पूर्ण क्रांति' से भटकाने में कामयाब रही थी। यह प्रकरण पूर्वोत्तर के एक राज्य सिक्किम से जुड़ा था। आजादी पश्चात् भी सिक्किम का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखा गया था और उसे भारतीय गणतंत्र के अंतर्गत एक अर्ध स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था जिसके अंतर्गत सिक्किम के राजा का अपने प्रदेश में पूरा अधिकार था और भारत की जिम्मेदारी केवल उसकी सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित थी। सिक्किम सामरिक दृष्टि से भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके पश्चिम में नेपाल तो उत्तर में तिब्बत है। आजादी के समय यहां चौग्याल वंश का शासन था। साठ के दशक से ही दो लाख की आबादी वाले इस राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने और राजशाही को समाप्त करने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। दूसरी तरफ तत्कालीन राजा पालदेन नामग्याल ने अपने राज्य को पूरी तरह से स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाने के प्रयास करने शुरू कर दिए थे। नामग्याल के इरादों से सतर्क इंदिरा सरकार ने सितम्बर १९७४ में राज्य में चुनाव करा विधानसभा गठन सत्ता चुने गए जनप्रतिनिधियों के हाथ सौंप राजा की समस्त शक्तियां समाप्त कर डाली थी। इसके साथ ही संविधान में संशोधन कर सिक्किम को भारतीय गणतंत्र का राज्य घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी के इस निर्णय को तब आम जन से काफी सराहना तो मिली लेकिन जेपी आंदोलन की धार कम नहीं हुई। जैसे-जैसे जेपी का आंदोलन तेज होता गया इंदिरा गांधी की मुश्किलें भी बढ़ती गईं। जेपी की सराहना करते हुए कांग्रेस के युवा नेता चंद्रशेखर ने 'यंग इंडिया' अखबार में एक लेख लिख प्रधानमंत्री को चेताने का प्रयास करने का साहस दिखा इन मुश्किलों में इजाफा कर डाला। उन्होंने लिखा 'जेपी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं इसलिए सत्ता के सहारे उनको नहीं हटाया जा सकता है। इस लड़ाई में वे स्वयं अपने को दांव में लगा देंगे और उससे जो तूफान उठेगा उसका सामना करने की क्षमता कांग्रेस में नहीं है।' अक्टूबर, १९७४ के दिन जेपी के आह्वान पर पचास हजार के करीब लोग महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर एकत्रित हुए। जहां से एक विशाल जुलूस के रूप में दिल्ली की सड़कों पर मार्च निकाला गया। आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शाम को प्रधानमंत्री से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने बिहार विधानसभा भंग करने की मांग इंदिरा गांधी के सम्मुख रखी जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। नवम्बर १९७४ की ४ तारीख को फिर एक बार पटना की सड़कों में विशाल जनसमूह उतर आया था। जेपी जब गांधी मैदान पहुंचे तो वहां तमाम सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद हजारों की संख्या में आंदोलनकारी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जेपी को बिहार पुलिस ने मंच में जाने से रोकने का प्रयास किया, छात्रों पर लाठी चार्ज किया जाने लगा था। इसी अफरा-तफरी में जेपी भी पुलिस की लाठी से चोटिल हो गए। उनकी दो पसलियां इस हमले में टूट गईं। लोकनायक पर हुए पुलिस उत्पीड़न से देशभर में इंदिरा सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा हो गया। हिंदी के ख्याति प्राप्त लेखक फणीश्वर नाथ 'रेणु' ने सरकार समक्ष अपना प्रतिरोध दर्ज कराते हुए उन्हें मिला पद्मश्री सम्मान वापस कर डाला। लेखक और कवि नागार्जुन ने अपनी सरकारी पेंशन का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी।'

नवम्बर १९७४ में कुछेक मित्रों की मध्यस्थता चलते इंदिरा और जेपी एक-दूसरे से मिले। यह मुलाकात लेकिन बेहद नकारात्मक रही। प्रधानमंत्री ने जयप्रकाश को विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने का आरोप लगा डाला। बकौल कैथरीन फ्रैंक-किसी प्रकार के समझौते के बजाय यह मुलाकात बेहद विस्फोटक और आरोप-प्रत्यारोप से भरी रही। इंदिरा ने नारायण पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए से धन लेने का आरोप लगाया। नारायण ने इंदिरा पर सोवियत संघ की मदद से तानाशाह बनने की बात कह डाली।

जनवरी, १९७५ की शुरुआत इंदिरा गांधी के लिए नई समस्या लेकर आई। भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त उनके करीबी सहयोगी रेलमंत्री ललित नारायण मिश्रा की २ जनवरी के दिन बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में एक बम विस्फोट के जरिए हत्या कर दी गई। मिश्रा इंदिरा सरकार के लिए भारी समस्या बन चुके थे इसलिए उनकी हत्या कराने का आरोप विपक्षी दलों ने सीधे प्रधानमंत्री पर लगाने में देरी नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन चलते ताकत पा रहीं 'विदेशी ताकतों' को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया था। प्रधानमंत्री का मानना था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी 'सीआईए' की मदद से 'आनंदमार्गियों' ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। १९५५ में प्रभात कुमार सरकार ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 'आनंदमार्ग प्रचार संघ' नामक संस्था की नींव रखी थी जिसका घोषित उद्देश्य अध्यात्म के जरिए आनंद की प्राप्ति करना था। सरकार के अनुसार 'तंत्र विद्या' के जरिए मनुष्य आत्मिक शांति और निर्वाण की अवस्था पा सकता है। साठ के दशक में इस संगठन का तेजी से विस्तार हुआ था। पश्चिम बंगाल में इस संगठन का टकराव वामपंथी संगठनों के साथ होने लगा था। इंदिरा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भी आनंदमार्गी खासे मुखर रहते थे और जयप्रकाश नारायण के समर्थन में काम करने लगे थे। १९७१ में इस संगठन के संस्थापक प्रभात कुमार सरकार को अपने ही पांच साथियों की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ललित नारायण मिश्रा की हत्या का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। हालांकि ३९ बरस तक चले मुकदमें बाद ८ दिसम्बर २०१४ को इस हत्या के आरोप में चार आनंदमार्गियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन हत्याकांड के सूत्रधारों की बाबत छाया संशय दूर न हो सका है। मिश्रा की हत्या ने इंदिरा गांधी को खासा विचलित करने का काम किया था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और इंदिरा मंत्रिमंडल के सदस्य रहे बसंत साठे के अनुसार- 'मिश्रा की हत्या से वे दहशतजदा हो गई थीं। वे इस संदेह में लगातार घिरती गईं कि उनके शत्रुओं से उनकी जान को खतरा है।' जयप्रकाश और उनके आंदोलन को इस हत्याकांड के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेवार मानने के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने इसे उनकी हत्या से पहले की गई 'ड्रेस रिहर्सल' करार देते हुए कह डाला-'जब मेरी हत्या होगी तो ये लोग (विपक्षी दल) मुझे मेरी ही हत्या का जिम्मेदार ठहरा देंगे।' जयप्रकाश नारायण अब खुले तौर पर बगावत की राह पकड़ चुके थे। १५ फरवरी १९७५ को दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की एक सभा में भाषण देते हुए उन्होंने सेना और पुलिस से 'अवैध और गलत आदेशों' का पालन न करने की अपील कर डाली।

क्रमशः

उत्तराखण्ड शासन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

युग पुरुष, उत्तराखण्ड के प्रणेता, जनप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री

"भारत रत्न"

स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी

की जयंती पर समस्त उत्तराखण्ड वासियों की ओर से

शत-शत नमन

पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

आरीएनीआई नी : UTTHIN/2009/29438, उत्तर प्रदेश : UP/GBDA58/2014-16